RNI No : MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 03, अंक 3 मासिक पत्रिका
25 मार्च 2024

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

मध्यम वर्ग

सामाजिक-आर्थिक विकास का वाहक

बांसगांव लोकसभा में हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका और साधना न्यूज के सर्व मैं 2024 के लिए हो रहे लोक सभा चुनाव मैं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता की पहली पसंद गोरखपुर निवासी, कमांडो कमल किशोर पूर्व सांसद बहराईच उत्तर प्रदेशऔर दिग्गज नेता। जनता का कहना है कि कांग्रेस ने यदि बहराईच पूर्व सांसद कमांडो कमल किशोर जी को टिकट देती है तो कमल किशोरजी भारी मतों से जीतेंगे अन्यथा यह कोई भी कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार हो बो यह सीट नहीं जीत पाएगा।

हमारा देश
हमाराअभिमान

25 मार्च 2024

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडो कमल किशोर (पूर्व सांसद)
- श्री के. कान्याल

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

विशेष संवाददाता
- रवि परिहार • रविकांत शर्मा

कानूनी सलाहकार
- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)

छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजौरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजौरिया
- हेमाटोलाजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादौन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट
- रागिनी चतुर्वेदी
- प्रवेंद्र चतुर्वेदी
- प्रखर सिंह

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर

मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन

मार्केटिंग मैनेजर
- सुनील • हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी ।
(सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	.....	02
शुभाशीष	.....	03
कवर स्टोरी	.....	04-05
देश	.....	06-07
देश	.....	08-09
प्रदेश	.....	10
इन्दौर	.....	11
देश-विदेश	.....	13
प्रदेश	.....	14
उज्जैन	.....	16
देश	.....	18-19
2023	.....	24
2024	.....	25
प्रदेश	.....	26
इन्दौर	.....	27
भोपाल-इन्दौर	.....	28
देश	.....	29
देश	.....	30
प्रदेश	.....	31
प्रदेश	.....	32-33
देश-प्रदेश	.....	34-35
देश	.....	36
प्रदेश	.....	37
आर्थिक	.....	40
शिक्षा	.....	44
अयोध्या	.....	45
मौसम	.....	46
ग्लैमर	.....	47-48

48

सुपरस्टार राम चरण के साथ शेयर करेंगी स्क्रीन जान्हवी

संपादकीय

चुनावी चंदे पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को मजबूत किया है

याचिकाकर्ताओं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) सहित अन्य ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुये इन सभी ने इस योजना को लागू करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2017 और फाइनेंस एक्ट 2016 में किए गए कई संशोधन को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए राजनीतिक दलों के लिए चंदा जुटाने की पुरानी इलेक्टोरल बांड स्कीम को अवैध करार देते हुए इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बांड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में गठित पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। अपने फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा है कि पॉलीटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी वह प्रक्रिया है जिससे मतदाता को वोट डालने के लिए सही चॉइस मिलती है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने तीन दिनों तक लगातार सुनवाई करने के बाद 2 नवंबर 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) सहित अन्य ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुये इन सभी ने इस योजना को लागू करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2017 और फाइनेंस एक्ट 2016 में किए गए कई संशोधन को गलत बताया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इससे राजनीतिक दलों को बिना जांच और टैक्स भरे फंडिंग मिल रही है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 के बजट में चुनावी इलेक्टोरल बांड स्कीम को पेश किया था।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

शुभाशीष

मोदी ने दुनिया को सनातन की विशिष्टि और शक्ति से परिचित करा दिया

मंदिर को 'शिल्प' और 'स्थापत्य शास्त्रों' में वर्णित निर्माण की प्राचीन शैली के अनुसार बनाया गया है। 'शिल्प' और 'स्थापत्य शास्त्र' ऐसे हिंदू ग्रंथ हैं, जो मंदिर के डिजाइन और निर्माण की कला का वर्णन करते हैं। मंदिर में वास्तुशिल्प पद्धतियों के साथ वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी और अब उन्होंने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। अयोध्या में उन्होंने जहां 500 साल पुराना हिंदुओं का सपना सच किया वहीं एक मुस्लिम देश यूएई में भी असंभव को संभव करके दिखा दिया। हम आपको बता दें कि अबू धाबी में जो पहला हिंदू मंदिर बना है उसके लिए पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात ने दान में दी। मंदिर का निर्माण कार्य 2019 में शुरु हुआ और अब इसके द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। अयोध्या से अबू धाबी तक के इस सफर में मोदी ने पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति से तो अवगत कराया ही है साथ ही सनातन की शक्ति का प्रदर्शन भी किया है। बात चाहे अयोध्या की हो या अबू धाबी की, दोनों ही जगह जिस तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी वह दर्शा रही है कि सिर्फ पुरानी ही नहीं बल्कि आज की पीढ़ी भी अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व करती है और उसके साथ जुड़ना चाहती है। अयोध्या के भव्य, नव्य और दिव्य राम मंदिर के बारे में तो आप सब जान ही चुके हैं इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि अबू धाबी में जिस पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है वह कैसा दिखता है। हम आपको बता दें कि इस मंदिर को वैज्ञानिक तकनीकों और प्राचीन वास्तुकला विधियों का उपयोग करके बनाया गया है। दुबई-अबू धाबी शेख जायेद हाइवे पर अल रहबा के समीप स्थित बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) द्वारा निर्मित यह हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस मंदिर में तापमान मापने और भूकंपीय गतिविधि पर नजर रखने के लिए उच्च तकनीक वाले 300 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं।

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

मध्यम वर्ग

सामाजिक-आर्थिक विकास का वाहक

मध्यम आय वर्ग में इजाफा होने का मतलब साफ-साफ यह हो जाता है कि देश की अर्थ व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसे यों समझा जा सकता है कि मध्यम आय वर्ग या दूसरे अर्थ में हम मध्यम वर्ग की बात करें तो जीवन जीने का कोई आनंद लेता है तो वह मध्यम वर्ग ही है।

माने या ना माने पर इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी देश के आर्थिक-सामाजिक विकास में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका रही है। यह केवल हमारे देश के संदर्भ में ही नहीं अपितु समूचे विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा तो कारण यही सामने आएगा। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका रही है। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से श्रमिक वर्ग उभर कर आया तो औद्योगिक क्रांति का ही बाई प्रोडक्ट मध्यम वर्ग का उत्थान माना जा सकता है। आर्थिक विश्लेषकों की माने तो आर्थिक विकास का कोई ग्रोथ इंजन है तो वह मध्यम वर्ग है। ज्यादा दूर नहीं जाए और केवल वर्तमान दशक की शुरुआत बल्कि 2021 की ही बात करें तो देश में 30 फीसद परिवार मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में आ गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि 2031 तक यह आंकड़ा बढ़कर 46 फीसद को छू जाएगा। यानी की इस दशक में बचे साढ़े पांच साल में भी मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में तेजी से सुधार होगा। 2021 में जहां 9.1 करोड़ परिवार मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में थे वहीं 2031 तक यह संख्या बढ़कर 16.9 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। किसी भी देश और उसकी अर्थ व्यवस्था के लिए यह अपने आप में किसी बढ़ी उपलब्धि से कम नहीं आंकी जा सकती। विशेषज्ञों के अनुसार 5 लाख से 38 लाख सालान आय वाले परिवारों को मध्यम आय वर्ग श्रेणी में माना गया है। यह भी समझना होगा कि मध्यम वर्ग का विस्तार का सीधा सीधा अर्थ गरीबी रेखा से लोगों का बाहर आना और बाजारु गतिविधियों में तेजी आने का कारण मध्यम वर्ग ही है। मांग और आपूर्ति को भी मध्यम वर्ग के संदर्भ में ही देखा और समझा जा सकता है।

मध्यम आय वर्ग में इजाफा होने का मतलब साफ-साफ यह हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसे यों समझा जा सकता है कि मध्यम आय वर्ग या दूसरे अर्थ में हम मध्यम वर्ग की बात करें तो जीवन जीने का कोई आनंद लेता है तो वह मध्यम वर्ग ही है। मध्यम वर्ग के लोग जीवन को जीने में विश्वास रखते हैं भले ही उन्हें ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत की मानसिकता के अनुसार जीवन यापन करना पड़ें। यही कारण है कि मध्यम वर्ग दिल खोलकर पैसा खर्च करता है। इसका एक कारण सामाजिक ताने बाने की भाषा में हम कहें तो यह कहा जा सकता है कि बहुत कुछ वह दिखावें के लिए करता है। जीवन यापन की दिखावे की इस प्रतिस्पर्धा में वह वो सब कुछ पाना चाहता है जो उसके परिवार, पड़ोसी, मित्रगण या आसपास के लोगों के पास है। इसमें रहन-सहन, खान-पान, पहनना-ओढ़ना, शिक्षा और इसी तरह की अन्य वस्तुओं/साधनों को प्राप्त करना मध्यम वर्ग का ध्येय रहता है और इसी कारण बाजार में नित नए उत्पादों की मांग बढ़ती है तो देष के लोगों के जीवन स्तर का पता चलता है।

दरअसल मध्यम वर्ग व्हाईट कॉलर का प्रतिनिधित्व करता है। वह इस प्रयास में रहता है कि दिन प्रतिदिन वह अधिक से अधिक साधन जुटाएं, भले ही उसके लिए उसे उधार का सहारा लेना पड़े। यहां यह भी समझ लेना जरुरी हो जाता है कि उच्च आय वर्ग की अपनी समझ व पहुंच होती है। पहली बात तो उच्च आय वर्ग की दायरें में कम लोग है। उनकी पसंद ना पसंद अलग होती है। उनके लिए जो उत्पाद बाजार में आएंगे वो अलग श्रेणी के होंगे। मध्यम वर्ग लगभग उसी दौड़ में दौड़ने का प्रयास करता है। उच्च वर्ग के पास लक्जिरियस चौपहिया वाहन है तो उसकी मांग पहले चरण में चौपहिया वाहन व उसके बाद ज्यों ज्यों वह थोड़ा आगे बढ़ना चाहेगा अपनी पहुंच के सुविधाजनक चौपहिया वाहन पाने की कोशिश में जुट जाएगा। इसी तरह से बाजार की मांग को मध्यम वर्ग ही बढ़ाता है। तस्वीर हमारे सामने हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं दो दशक ही हुए होंगे कि घरों में पंखों की जगह कूलरों ने ली और कूलरों में भी हैसियत अनुसार ब्राण्डेड कंपनियों से लेकर लोकल कंपनियों के कूलरों ने घरों में जगह बनाई। आज तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आ गया है जिस एयर कण्डीशनर के लिए केवल सोचा जा सकता था वह आज घर घर में पहुंच गया है। कम से कम एक एसी तो मध्यम वर्गीय परिवार में देखने को आसानी से मिल जाएगा। इसे यों समझा जा सकता है कि मध्यम वर्ग के विस्तार के अनुसार बाजार में मांग बढ़ी तो नित नई कंपनियां बाजार में आई और इससे अर्थ व्यवस्था को गति मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़े। यह तो एक उदाहरण मात्र है। देखा जाए तो फास्टफूड हो या कंफेक्सरी या शॉफ्ट ड्रिंक या इसी तरह की अन्य खाने पीने की चीजें इसको बाजार मिला है तो इसका श्रेय मध्यम वर्ग को ही जाता है। पर्सनल केयर आइटम्स की मांग और आपूर्ति भी मध्यम वर्ग के कारण ही बढ़ी है। आज ओन लाईन का जो बाजार खड़ा हुआ है उसको गति दी है तो वह मध्यम आय वर्ग के लोगों ने ही दी है। स्कूटर, स्कूटी, कार से लेकर वाहनों की जो रेलम पेल देखी जा रही है वह इस मध्यम वर्ग के कारण ही है।

रियल स्टेट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और गगनचुंबी इमारतों का जिस तरह से जाल बिछ रहा है वह मध्यम वर्ग के कारण ही संभव हो पा रहा है। यही कारण है कि आज देशी विदेशी कंपनियां मध्यम वर्ग को केन्द्रीत कर अपने उत्पादों को बाजार में उतार रही है। सही मायने में कहा जाये तो जिसने मध्यम वर्ग की मांग को समझा वह मालामाल होता जा रहा है और उसकी बाजार में पकड़ तेज होती जा रही है। ऐसे में यह मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था का बहुत कुछ श्रेय मध्यम वर्ग को जाता है।

क्या होती है आदर्श आचार संहिता, क्यों और कब की जाती है लागू

चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है।

चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान कर दिया। तारीखों के एलान के साथ ही देशभर में आचार संहिता लागू हो गई। इससे पहले आयोग ने एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें धन और बाहुबल पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ चलने की भी बात कही गई है। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान कर दिया। तारीखों के एलान के साथ ही देशभर में आचार संहिता लागू हो गई। इससे पहले आयोग ने एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें धन और बाहुबल पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ चलने की भी बात कही गई है। आइये जानते हैं कि यह आचार संहिता आखिर होती क्या है? यह किसके लिए जारी की जाती है? किन-किन चीजों पर लगती है पाबंदी?

आदर्श आचार संहिता क्या है?

आदर्श आचार संहिता राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनैतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावोंका आयोजन चुनाव आयोग का सांविधिक कर्तव्य है।

आदर्श आचार संहिता कितने दिनों तक लागू रहती है?

चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है।

आदर्श आचार संहिता की विशेषताएं?

इसकी मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती हैं कि राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभायात्राओं, मतदान दिन की गतिविधियों और सत्ताधारी दल के कामकाज भी संहिता से निर्धारित होते हैं।

मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के साथ नहीं मिलाएंगे और न ही चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी तंत्र या कार्मिकों का प्रयोग करेंगे। हालांकि, चुनाव प्रचार दौरे के साथ आधिकारिक दौरे को मिलाने संबंधी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान से प्रधानमंत्री को छूट है।

विमान, वाहनों इत्यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या उम्मीदवार के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

सरकार के लिए क्या नियम होते हैं?

चुनाव के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो पहले आयोग की अनुमति ली जाएगी।

मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा। इसमें शर्त है कि इस प्रकार के सफर को किसी चुनाव प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ा जाए।

चुनाव प्रचार के लिए क्या नियम हैं?

चुनाव आयोग के अनुसार, कोई दल या उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो धार्मिक या भाषायी जातियों और समुदायों, के बीच मतभेद को बिगाड़े या परस्पर घृणा या तनाव उत्पन्न करे। जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, तो उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम, विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जाएगा। दल और उम्मीदवार दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के सभी पहलुओं की आलोचना करने से दूर रहें। इसमें शर्त है कि ये पहलु किसी के सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं होने चाहिए। तोड़-मरोड़ कर या असत्यापित आरोपों के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

सभी दल और प्रत्याशी ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं। ये गतिविधियां हैं मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, हमशक्ल मतदाता से मतदान करवाना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी

के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन की व्यवस्था करना।

प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल और प्रत्याशी उसके राजनीतिक मत या गतिविधियों को कितना भी नापसंद क्यों न करते हों। लोगों के मत या गतिविधियों के प्रति विरोध जताने के लिए उनके घरों के सामने किसी भी परिस्थिति में न तो प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और न ही धरना दिया जाएगा।

कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा।

राजनैतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में न तो बाधा खड़ी करें और न ही उन्हें भंग करें। एक दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जहां दूसरे दल द्वारा बैठकें आयोजित की गई हों। एक दल के द्वारा लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जाएंगे।

चुनाव प्रचार के लिए क्या?

आयोग ने राजनीतिक प्रयोग के लिए स्कूलों और कॉलेज के मैदानों (पंजाब और हरियाणा राज्य को छोड़कर जहां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से विशेष निषेध है) के प्रयोग की अनुमति नहीं दी है।

सार्वजनिक संपत्ति पर उम्मीदवार संबंधित पार्टी अथवा उम्मीदवार के पोस्टर, प्लेकार्ड, बैनर, ध्वज आदि को लागू स्थानीय कानून के प्रावधानों और निषेधात्मक आदेशों के अध्यधीन प्रदर्शित कर सकता है।

उम्मीदवार चुनाव के समापन के लिए तय किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सिनेमा, टेलीविजन या अन्य इसी तरह के उपकरण के माध्यम से जनता को किसी भी चुनाव सामग्री अथवा प्रचार को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारियों की किसी चुनावक्षेत्र में उपस्थिति पर प्रतिबंध है। प्रचार बंद होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारी आदि, जो चुनाव क्षेत्र के बाहर से आए हैं और जो चुनाव क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें चुनाव क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए। रात 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जन सभाएं सुबह 6.00 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार प्रचार बंद होने के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते।

मतदान केंद्र के लिए क्या?

मतदान के दिन मतदान केंद्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर वोटों के लिए प्रचार करना निषिद्ध है। मतदान के दिन मतदान केंद्र के आस-पास किसी भी तरह के हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था अपराध है।

इस चुनाव में 96.8 करोड़ मतदाता, 2019 के मुकाबले 6 फीसद बढ़े

जानें महिला-पुरुष और युवा वोटर कितने?

देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया गया है। इस दौरान आयोग ने आम चुनावों के लिए पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़े भी जारी किए। ईसीआई के अनुसार, देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 96.88 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया गया है। इस दौरान आयोग ने आम चुनावों के लिए पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़े भी जारी किए। ईसीआई के अनुसार, देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 96.88 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं।

आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। चुनाव आयोग ने 1 जनवरी, 2024 को अर्हता तिथि के संदर्भ में ये आंकड़े जारी किए हैं। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के मुताबिक, देशभर में कुल 96.88 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। इस तरह से विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग हमारे देश में है। 2019 में यह आंकड़ा 89.6 करोड़ था।

देश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 46.5 करोड़ था। दूसरी ओर महिला मतदाता 47.1 करोड़ हैं जो पिछले चुनाव में 43.1 करोड़ थी। चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाता सूची में लिंगानुपात सकारात्मक रूप से बढ़ा है। यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का संकेत भी देता है। मतदाता सूची में 2.63 करोड़ से अधिक नए मतदाताओं को शामिल किया गया है। इनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला मतदाता जबकि 1.22 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। इस तरह से नए महिला मतदाताओं की संख्या नए पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 15% अधिक है।

बीते पांच वर्षों (2019-2024) में मतदाता लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। लिंगानुपात 2019 में 928 था जो 2020 में बढ़कर 932 और 2021 में 935 हो गया। 2022 और 2023 में यह 940 ही रहा। वहीं 2024 में बढ़कर 948 हो गया है।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में युवाओं की भूमिका काफी अहम होती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, देश में 18-19 आयु वर्ग के 1.85 करोड़ युवा मतदाता हैं। पिछली बार यह आंकड़ा 1.5 करोड़ था। 18-19 और 20-29 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। ईसीआई ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विशेष सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) नियुक्त किए गए थे ताकि शैक्षणिक संस्थानों से सीधे युवाओं के नामांकन की सुविधा मिल सके। इसके अलावा 17 साल से अधिक युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन भी मांगे गए हैं। साल में मिलने वाले तीन मौकों पर कुल 10.64 लाख से अधिक अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मौजूदा समय में देशभर में दिव्यांग मतदाता 88.35 लाख हैं। वहीं बीते लोकसभा चुनाव के दौरान 45.64 लाख PwD मतदाता थे। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान के दिन पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करके दिव्यांग व्यक्तियों का समर्थन करने का एक सराहनीय प्रयास किया गया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि देशभर में 48,044 अन्य मतदाता हैं। वहीं 2019 में अन्य मतदाता 39,683 थे। ईसीआई ने जानकारी दी है कि घर-घर सत्यापन के बाद 1,65,76,654 मृतकों, स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लिकेट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसमें 67,82,642 मृत मतदाता, 75,11,128 स्थायी रूप से स्थानांतरित/अनुपस्थित मतदाता और 22,05,685 डुप्लिकेट मतदाता शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि कमजोर जनजातीय समूहों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के 100% पंजीकरण को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इससे मतदाता सूची अब तक की सबसे समावेशी बन गई है।

पांचवीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद क्या होगी पुतिन की रणनीति..?

US समेत कई देश नतीजे के विरोध में क्यों?

रूस में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो गया है और अब नतीजे भी सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर जीत मिली है। युद्धग्रस्त देश में हुए चुनाव पर दुनियाभर की नजरें टिकी रहीं। पुतिन ने राष्ट्रीय जनमत संग्रह के जरिए में पांचवीं बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता बना लिया है।

रूस में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो गया है और अब नतीजे भी सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर जीत मिली है। युद्धग्रस्त देश में हुए चुनाव पर दुनियाभर की नजरें टिकी रहीं। पुतिन ने राष्ट्रीय जनमत संग्रह के जरिए में पांचवीं बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता बना लिया है। उधर सोमवार को नतीजों की घोषणा होने के बाद पुतिन ने अपने पहले संबोधन में पश्चिमी देशों को धमकी दी। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन में अगर संघर्ष हुआ तो इसका मतलब ये है कि यह दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध से महज एक कदम दूर होगी।

रूस के राष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ है?

व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को रूस के राष्ट्रपति चुनाव में एक रिकॉर्ड जीत हासिल की। इस जीत से सत्ता पर उनकी पहले से ही मजबूत पकड़ मजबूत हो गई। देश में जनमत संग्रह के जरिए तीन दिन तक मतदान की प्रक्रिया चली। मतदान सर्वेक्षक संस्था पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन (एफओएम) के एग्जिट पोल के मुताबिक, पुतिन ने 87.8% वोट हासिल किए। यह रूस के सोवियत इतिहास के बाद का सबसे बड़ा परिणाम है। रशियन पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर (वीसीआईओएम) ने पुतिन को 87% पर रखा है। नतीजों के अनुसार, कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव दूसरे स्थान पर रहे। निकोलाई को महज 4% वोट ही मिले। वहीं नवागंतुक व्लादिस्लाव दावानकोव तीसरे और लियोनिद स्लतस्की चौथे स्थान पर रहे।

चुनाव कैसे हुए थे? : रूसी चुनाव ठीक दो साल बाद हुआ है। करीब दो साल पहले 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच घातक युद्ध शुरू हुआ था। तीन दिवसीय चुनाव पर युद्ध की तलवार लटक रही है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने रूस में तेल रिफाइनरियों पर बार-बार हमला किया, रूसी क्षेत्रों पर गोलाबारी की और रूसी सीमाओं को भेदने की कोशिश की।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रव्यापी मतदान 74.22% था। यह आंकड़ा 2018 के 67.5% के मतदान से भी ज्यादा था। यह चुनाव हजारों पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा के बीच कराया गया। रूस में

चुनाव के लिए 11.4 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। रॉयटर्स के मुताबिक मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और येकातेरिनबर्ग में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं, विशेष रूप से युवा लोगों की कतारें थीं। पिछले दो दिनों में विरोध की घटनाएं भी हुईं। कई जगह मतदान केंद्रों में आग लगा दी गई या मतपेटियों में हरा रंग डाल दिया गया। विरोधियों ने खराब हुए मतपत्रों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पोस्ट कीं। समूह ओवीडी-इन्फो के अनुसार, पूरे रूस में रविवार को कम से कम 74 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

नतीजों के बाद पुतिन ने क्या कहा?

इस जीत के साथ पुतिन राष्ट्रपति के रूप में एक और पारी खलने के लिए तैयार हैं। 71 वर्षीय पुतिन छह साल के नए कार्यकाल पूरा करने पर जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ देंगे। वह 200 से अधिक वर्षों तक रूस के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले नेता बन जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके पुतिन पहली बार 1999 में सत्ता में आए थे। जीत के बाद पुतिन ने मॉस्को में अपने समर्थकों के बीच एक विजयी भाषण दिया। उन्होंने समर्थकों से कहा कि वह यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान से जुड़े कार्यों को हल करने को प्राथमिकता देंगे और रूसी सेना को मजबूत करेंगे। पुतिन ने कहा, 'हमारे सामने कई काम हैं। हमें डराने वाला और हमें दबाने वाला इतिहास में कोई भी कभी सफल नहीं हुआ है। वे अब भी सफल नहीं हुए हैं और वे भविष्य में भी कभी सफल नहीं होंगे।' पुतिन ने संवाददाताओं से कहा कि वह रूस के चुनाव को लोकतांत्रिक मानते हैं और कहा कि उनके खिलाफ नवलनी-प्रेरित विरोध का चुनाव के नतीजे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

दुनिया के देशों ने पुतिन की जीत पर क्या कहा?

रूस में संपन्न हुए चुनाव पर दुनियाभर की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पश्चिमी देशों ने चुनावों की आलोचना की है। रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि पुतिन हमेशा के लिए शासन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'चुनाव की कोई वैधता नहीं है और न ही हो सकती है।' अमेरिका ने चुनाव को लेकर कहा कि ये स्पष्ट रूप से न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष थे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, 'चुनाव स्पष्ट रूप से स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं हैं क्यों पुतिन ने राजनीतिक विरोधियों को कैसे कैद किया और दूसरों को उनके खिलाफ लड़ने से रोका।' जर्मनी ने भी रूस में चुनाव को स्वतंत्र है और निष्पक्ष मानने से इनकार किया है और कहा कि परिणाम किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि पुतिन का शासन सेंसरशिप, दमन और हिंसा पर निर्भर है। यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में चुनाव अमान्य और अंतरराष्ट्रीय कानून का एक और उल्लंघन है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति चुने जाने पर पुतिन को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा, 'आगामी वर्षों में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।' हालांकि, चीन ने रूसी चुनावों पर पुतिन का समर्थन किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन की जीत उनके लिए लोगों के समर्थन को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि चीन, रूस के साथ आगे करीबी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए तैयार है।

सनातन का संदेश देता है भारतीय नववर्ष...

भारतीय की संस्कृति में पुरातन काल से नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही माना जाता रहा है। इस तिथि को भारतीय संस्कृति में अति पावन दिन माना गया है। क्योंकि इसी प्रतिपदा दिन रविवार को सूर्योदय होने पर ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण की शुरुआत की थी।

अंग्रेजी नव वर्ष के बढ़ते प्रभाव के बीच राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भारतीय नागरिकों को सचेत करते हुए लिखते हैं कि ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्यौहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये त्यौहार नहीं। इन पंक्तियों का आशय पूरी तरह से स्पष्ट था कि अंग्रेजी नव वर्ष हमारा अपना नहीं, बल्कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयता को मिटाने के लिए भारत पर थोपा गया था। विसंगति यह है कि अंग्रेज जो भारत में छोड़कर गए थे, उसे हमने अपना मान लिया। उसके पीछे मूल कारण यही था कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को विस्मृत कर चुके थे। अपने स्वत्व का बोध भी हमको नहीं रहा था। जब हम स्वत्व की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसमें वह सब दिखाई देगा, जो मूल भारत की कल्पना था।

अपना मूल भारत क्या था? क्या हमें इसका भान है? यकीनन नहीं, क्योंकि आज जो भारत दिख रहा है, उसे पहले मुगलों ने अपने हिसाब से बनाया और फिर अंग्रेजों ने भारतीय समाज को हमें अपनी संस्कृति से विमुख कर दिया। विचार कीजिए कि भारत का स्वत्व क्या है? अगर भारत का स्वत्व जानना है तो हमें मुगलों से पूर्व के भारत का अध्ययन करना होगा, वही वास्तविक भारत है। आज हम भले ही अंग्रेजी दिनचर्या का उपयोग करते हैं, लेकिन आज भी यह सत्य है कि अंग्रेजी दैनंदिनी का प्रयोग हम अपने त्यौहारों में कभी नहीं करते। क्योंकि हमारे सारे त्यौहार सांस्कृतिक और प्राकृतिक हैं। वे प्रकृति के हिसाब से ही तय किए जाते हैं। इसीलिए प्रारंभ से ही भारत के समस्त त्यौहार दिशा बोध कराने वाले रहे हैं। वसंत के त्यौहार को ही ले लीजिए, इसमें प्राकृतिक बोध होता है। वसंत के पश्चात पतझड़ और फिर प्रकृति में नवीनता का उल्लास। यही उल्लास प्राकृतिक नव वर्ष का आभास कराता है। इसीलिए यही भारत का अपना नव वर्ष है, अंग्रेजों वाला नहीं।

भारतीय की संस्कृति में पुरातन काल से नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही माना जाता रहा है। इस तिथि को भारतीय संस्कृति में अति पावन दिन माना गया है। क्योंकि इसी प्रतिपदा दिन रविवार को सूर्योदय होने पर ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण की शुरुआत की थी। इसलिए इसको सृष्टि का प्रथम दिवस भी कहते हैं। यह प्राकृतिक संयोग ही है कि अब भारत के नागरिक अपनी मूल की ओर लौट रहे हैं। जो लोग कल तक अपने नव वर्ष मनाने वाले समाज की हंसी उड़ाता था, वे स्वयं होकर नव वर्ष मनाने की ओर प्रवृत हो रहे हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत अपने स्वत्व की ओर लौट रहा है। भारत के नागरिकों को यह आभास होने लगा है कि हमारा देश किसी भी मामले में दुनिया के देशों से पीछे नहीं रहा, बल्कि उसे षड्यंत्र पूर्वक पीछे कर दिया गया था। अब यह षड्यंत्र भी समझ में आने लगा है। इसलिए अब बहुत बड़ी संख्या में भारत का अपना नव वर्ष मनाने के लिए एकत्रित होने लगे हैं।

वर्तमान में जिस प्रकार से श्रद्धा केन्द्रों पर भीड़ बढ़ रही है, वह इस बात का प्रमाण है कि भारत का युवा जाग्रत हो रहा है। उसे सांस्कृतिक रूप से अपने पराए का बोध हो रहा है। समाज अपने विवेक से श्रेष्ठ और बुराई के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने लगा है। समाज के व्यवहार में भी व्यापक परिवर्तन आया है। जो बुद्धिजीवी पहले हर बात की अपने हिसाब से व्याख्या करते थे, आज वे भी भारतीय संस्कृति के अनुसार चलते की ओर प्रवृत हुए हैं। इसलिए अब भारतीय समाज को भ्रमित करने के दिन बहुत दूर जा चुके हैं।

आज विश्व के कई देशों के नागरिक अपनी भोगवादी विकृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से आस्था के क्षेत्र के रूप में विद्यमान नगरों में यह दृश्य आम हो गए हैं। आज गंगा के घाट पर विदेशी नागरिक भजन करते हुए मिल जाते हैं तो ब्रज की गलियों में कृष्ण भक्ति में लीन अनेक विदेशी नागरिक भी दिखाई देते हैं। भारत की संस्कृति में इस बात की स्पष्ट कल्पना है कि भगवादी विकृति से मन विकृत हो जाता है। आत्मा की शुद्धि करना है तो उसके लिए भारतीय संस्कृति ही सर्वोत्तम है। जब विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को पसंद करके उसकी राह पर चलने के लिए आगे आ रहे हैं, तो फिर यह हमारी अपनी है। यह हमारा स्वत्व है। इसलिए हम अपना नव वर्ष धूमधाम से मनाएं और अपने जीवन को सफल करें।

लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान में पक रही है सियासी खिचड़ी...

भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें राजस्थान से 15 नाम शामिल हैं। एक रणनीतिक विकल्प के रूप में समझे जाने वाले कदम में, सत्तारूढ़ दल ने 2019 के आम चुनावों में विजयी हुए कई उम्मीदवारों को बनाए रखने का विकल्प चुना है।

भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें राजस्थान से 15 नाम शामिल हैं। एक रणनीतिक विकल्प के रूप में समझे जाने वाले कदम में, सत्तारूढ़ दल ने 2019 के आम चुनावों में विजयी हुए कई उम्मीदवारों को बनाए रखने का विकल्प चुना है। विशेष रूप से, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे, दुष्यंत सिंह को झालावाड़-बारां लोकसभा क्षेत्र के लिए फिर से नामांकित किया गया है, जहां वह वर्तमान में संसद सदस्य का पद संभाल रहे हैं।पिछले दिसंबर में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे को किनारा किए जाने के बाद अटकलें शुरू हो गई थी कि वसुंधरा राजे और भाजपा के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा हैं। वसुंधरा राजे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में भी शामिन नहीं हो रही थी। ऐसे में अब जब जीत की हेट्रिक लगाने वाले वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह राजे को फिर से भाजपा ने टिकट दिया है तो माना जा रहा है कि पार्टी और राजे की बीच सब कुछ ठीक हो गया हैं। दुष्यंत सिंह को टिकट मिलने के बाद से ही राजे को पार्टी के कई कार्यक्रमों में दी देखा गया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पहली सूची में राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीट में से 15 सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इन 15 में से सात लोकसभा सीट पर नए चेहरे उतारे जाने से शेष मौजूदा सांसदों का भविष्य भी अधर में दिख रहा है। आगामी आम चुनाव में सभी 25 सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिहाज से हाईकमान के पास 'चुनाव जीतने की क्षमता' नामक एक कारक है जो पार्टी के लिए सर्वोपरि है। भाजपा ने शनिवार को घोषित पहली सूची में आठ मौजूदा सांसदों को बरकरार रखा है और सात सीट पर नए चेहरों को टिकट दिया है। दो सांसदों के वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सात में से दो सीट पहले से रिक्त थीं। भाजपा की पहली सूची में बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़-बारां के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जबकि अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, करौली-धौलपुर, राजसमंद और टोंक-सवाई माधोपुर के लिए टिकटों की घोषणा का इंतजार है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 24 सीट जीती थीं और उसके गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने नागौर सीट से जीत दर्ज की थी। इस तरह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजद) ने सभी 25 सीट पर जीत हासिल कर ली थी। बेनीवाल की आरएलपी अब राजग की सहयोगी नहीं है और वह खुद वर्तमान में विधायक हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर सभी 25 सीट पर जीत दर्ज की थी। भाजपा ने पहली सूची में तीनों केंद्रीय मंत्रियों - गजेंद्र सिंह शेखावत (जोधपुर), अर्जुन मेघवाल (बीकानेर) और कैलाश चौधरी (बाड़मेर) के साथ-साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (कोटा-बूंदी), भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी को बरकरार रखा है। लेकिन सी पी जोशी (चित्तौड़गढ़), सुमेधानंद सरस्वती (सीकर), पीपी चौधरी (पाली) और दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां) का टिकट दिया गया है। जिन मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं उनमें राहुल कस्वां (चूरू), रंजीता कोली (भरतपुर), देवजी पटेल (जालौर), अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर) और कनकमल कटारा (बांसवाड़ा) शामिल हैं, पिछले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता बाबा बालक नाथ के जीतने पर अलवर सीट खाली हुई है। इसी तरह आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के विधायक बनने पर नागौर सीट खाली हुई है।

चूरू से दो बार के सांसद राहुल कस्वां और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच मतभेद साफ नजर आ रहे थे और माना जा रहा है कि अंदरूनी कलह के कारण ही उनका टिकट काटा गया है। विधानसभा चुनाव में राठौड़ की हार के लिए कस्वां को जिम्मेदार ठहराया गया था। चूरू सीट पर राहुल कस्वां की जगह पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया को नये चेहरे के रूप में टिकट दिया गया है, जबकि देवजी पटेल, जो 2023-विधानसभा चुनाव हार गए थे, की जगह लुंबाराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुईं ज्योति मिर्धा को नागौर सीट से टिकट मिला है। टिकट पाने वाले अन्य नए लोगों में महेंद्रजीत सिंह मालवीय (बांसवाड़ा), मन्नालाल रावत (उदयपुर) और रामस्वरूप कोली (भरतपुर) का नाम शामिल है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री मालवीय भी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। बाबा बालकनाथ के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई अलवर सीट पर पार्टी ने राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव को टिकट दिया है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि टिकट तय करने के लिहाज से पार्टी के लिए 'जीतने की क्षमता' ही एकमात्र मानदंड है। पार्टी ने सभी 25 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय स्तर पर राजग 300 सीट के आंकड़े को पार कर जाए। उन्होंने बताया कि 'जीतने की क्षमता' का आकलन करने के लिए सर्वेक्षणों और विभिन्न स्तरों पर प्राप्त 'फीडबैक' और अन्य विभिन्न मानदंडों के तहत सांसद के व्यक्तिगत प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है और उसी के आधार पर टिकट तय करने की कवायद की गई है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बाकी सीट पर इस हफ्ते फैसला ले लिया जाएगा। शेष 10 सीट में से दो, जयपुर ग्रामीण और राजसमंद भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौड़ और दीया कुमारी के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई हैं। इन सीट पर नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा। अजमेर सीट से सांसद भागीरथ चौधरी और झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार विधानसभा चुनाव हार गए थे और संभावना है कि उन्हें बदला जा सकता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलने की संभावना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद से टिकट मिल सकता है और पूनिया को अजमेर या जयपुर ग्रामीण सीट से मैदान में उतारा जा सकता है।

बांसगांब लोक सभा चुनाव के लिए क्षेत्र की जनता की पहली पसंद

कमांडो कमांडो कमांडो

Exclusive

• **मनोज चतुर्वेदी** संपादक
हमारा देश हमारा अभिमान

बांसगांव लोकसभा में हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका,और साधना न्यूज के सर्वे मैं 2024 के लिए हो रहे लोक सभा चुनाव मैं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता की पहली पसंद निवासी राजधानी तहसील चौरी चौरा जिला गोरखपुर, कमांडो कमल किशोर पूर्व सांसद बहराईच उत्तर प्रदेश और दिग्गज नेता एवं सामाजिक नेता जनता की पहली पसंद बनके उभरे है जनता के बीच कमांडो कमांडो कमांडो चल रहा है तथा जनता का कहना है कि हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय कमांडो कमांडो कमांडो है। जनता के यह कहने के पीछे एक कारण यह भी है की पूर्व सांसद की छवि ईमानदार ,मिलनसार और हर समय उपस्थित रहने बाली है। साथ ही सर्वे मैं यह भी बात उभर के आई है की जनता मैं कमांडो को एक देश की सेना के सैनिक के रूप मैं और

छवि देश के प्रहरी और ईमानदर व्यक्तित्व के रूप में होती । इन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी सर्विस और पद को छोड़ कर देश की जनता की सेवा का माध्यम से देश की सेवा का मन बनाया। जनता का कहना है कि कांग्रेस ने यदि बहराइच पूर्व सांसद कमांडो कमल किशोर जी को टिकट देती है तो कमल किशोरजी भारी मतों से जीतेंगे अन्यथा इस लोक सभा सीट पर कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार हो, वो यह सीट नही जीत पाएगा। इस सर्वे मैं महिलाओं,पुरुषों और युवाओं की पहली पसंद के रूप मैं कमांडो कमल किशोर ही उभरे है। इसके पीछे इनका बहराइच मैं सांसद रहते हुए विकास कार्य कराने के साथ साथ ही अपने गांव, तहसील,जिला के लोगो के लिए भी उपलब्ध रहते हुए सर्व समाज की समस्याओं को भी दूर करना, विकास कार्य करना भी बांस गांव लोक सभा क्षेत्र की जनता को पसंद आया है। इसलिए यह बांसगांव की जनता की पहली पसंद है। यह पहले भी इस क्षेत्र से सांसद का चुनाव 1999 लड़ चुके है। और तभी से इस लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच परिवार के सदस्य के रूप मैं उपस्थित। कोड़ी राम,गोलाबाजार, बासगांव कसवा, बड़हल गंज, बरहज, मदनपुर, रुद्रपुर, चौरी चौरा, नई बाजार, गोबरोल चौहराहा कुलुआ तारा आदि सैकड़ों गांव के सर्वे मैं यह बात उभर के आई। यह सर्वे सटीक सर्वे है।

इस बार चुनाव में कितना खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार...

हाल में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि उन्होंने आगामी चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दिए गए प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि उनके पास 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए 'इतना पैसा नहीं है'। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि एक चुनाव लड़ने में प्रत्याशी कितना तक खर्चा कर सकता है। यही हम आपकों बताते हैं। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग (ईसी) की प्रमुख जिम्मेदारियों में अपने स्वयं के पर्यवेक्षकों और राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से पार्टियों और व्यक्तिगत उम्मीदवारों दोनों द्वारा चुनाव खर्च की निगरानी करना है। लोकसभा क्षेत्रों के लिए, उम्मीदवारों को 95 लाख रुपये तक सीमित रखा गया है, जबकि विधानसभा सीटों के लिए, सीमा 40 लाख रुपये है। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक दलों के लिए खर्च की कोई सीमा नहीं है।

कुछ छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीमा क्रमशः 75 लाख रुपये और 28 लाख रुपये है। पिछले कुछ वर्षों में खर्च की सीमा बढ़ाई गई है, जिसमें 2019 भी शामिल है, जब लोकसभा उम्मीदवारों के लिए यह 70 लाख रुपये और विधानसभा दावेदारों के लिए 28 लाख रुपये थी। व्यय सीमा से तात्पर्य उस अधिकतम राशि से है जो एक उम्मीदवार सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टरों, बैनरों और वाहनों जैसी चुनाव-संबंधी गतिविधियों पर कानूनी रूप से खर्च कर सकता है। इसमें चुनाव प्रचार से जुड़ी सभी लागतें शामिल हैं। चुनाव के समापन के बाद, उम्मीदवारों को 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग (ईसी) को अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

चुनाव निकाय अक्सर खर्च सीमा को संशोधित करता है, और सीमा को पिछली बार 2022 में संशोधित किया गया था। उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा में आखिरी बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था, जिसे 2020 में 10 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया था। समिति ने राजनीतिक दलों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों से सुझाव आमंत्रित किए थे और पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है। इसमें चुनाव प्रचार के बदलते तरीकों को भी शामिल किया गया है, जो धीरे-धीरे आभासी अभियान की ओर बढ़ रहा है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा बार-बार संशोधन के अधीन है, जो मुख्य रूप से लागत विचार और बढ़ती मतदाता आबादी से प्रभावित है।

कब क्या रही सीमा

1951-52: पहले आम चुनाव में, लोकसभा उम्मीदवारों को अधिकतम 25,000 रुपये खर्च करने की अनुमति थी, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 10,000 रुपये थी।

1971: अधिकांश राज्यों के लिए खर्च सीमा बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी गई।

1980: सीमा बढ़ाकर प्रति उम्मीदवार 1 लाख रुपये कर दी गई। 1984: कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये और छोटे राज्यों में 1.3 लाख रुपये कर दिया गया। एक से दो सीटों वाले राज्यों में अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये रही, जबकि चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में यह सीमा 50,000 रुपये थी।

1996: उदारीकरण के बाद के चुनाव में अधिकांश राज्यों के लिए सीमा को तीन गुना बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये कर दिया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति और सीटों की संख्या के आधार पर बदलाव किया गया।

1998: खर्च सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये की गई।

2004: बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया।

2014: दोगुना से अधिक बढ़कर 70 लाख रुपये।

2022: 2019 के चुनावों के बाद, खर्च की सीमा को मौजूदा आंकड़ों तक बढ़ा दिया गया।

चिंताजनक : वैज्ञानिकों का खुलासा

प्लास्टिक में 16 हजार से अधिक रसायन, इसमें चार हजार 200 सबसे खतरनाक

नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल के सहयोग से तैयार की गई स्टेट ऑफ द साइंस ऑन प्लास्टिक केमिकल्स नामक रिपोर्ट के मुताबिक, जितने भी तरह के प्लास्टिक का अध्ययन किया गया है वे सभी हानिकारक रसायन छोड़ते हैं। कभी बेहद उपयोगी समझा जाने वाला प्लास्टिक आज दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। प्लास्टिक में 16,325 रसायन मौजूद हैं। इनमें 26 फीसदी यानी 4,200 रसायन इन्सानों और पर्यावरण दोनों के लिए भारी नुकसानदेह हैं। यूरोप के वैज्ञानिकों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने प्लास्टिक में करीब 13,000 रसायनों की पहचान की थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इनमें से केवल छह फीसदी रसायन ऐसे हैं, जिन्हें वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनियमित किया जाता है। इसके अलावा कई खतरनाक रसायनों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल के सहयोग से तैयार की गई स्टेट ऑफ द साइंस ऑन प्लास्टिक केमिकल्स नामक रिपोर्ट के मुताबिक, जितने भी तरह के प्लास्टिक का अध्ययन किया गया है वे सभी हानिकारक रसायन छोड़ते हैं। कभी बेहद उपयोगी समझा जाने वाला प्लास्टिक आज दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। बुनियादी जानकारी का आभाव... रिपोर्ट के मुताबिक, प्लास्टिक में पाए जाने वाले एक चौथाई से अधिक ज्ञात रसायनों की पहचान के बारे में बुनियादी जानकारी का अभाव है। आधे से अधिक के बारे में उनके कार्यों और

प्रयोगों के बारे में पब्लिक डोमेन में अस्पष्ट जानकारी है। कौन सा देश कितने प्लास्टिक का उत्पादन कर रहा है और कितना प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है, इस बारे में भी आंकड़ों का आभाव है। यह बेहद चिंताजनक है कि 10 हजार से अधिक रसायनों से जुड़े खतरों को लेकर जानकारी का आभाव है। प्लास्टिक में उपयोग के लिए 1,300 से अधिक रसायनों का व्यापार किया जाता है और अच्छी तरह से अध्ययन किए गए प्लास्टिक प्रकारों में पाए जाने वाले 29 से 66 फीसदी रसायन चिंता का विषय हैं। यानी पैकेजिंग से लेकर सामान्य इस्तेमाल तक के प्लास्टिक के सभी प्रमुख प्रकारों में 400 से अधिक खतरनाक रसायन मौजूद हैं।

वैश्विक स्तर पर हर साल करीब 40 करोड़ टन प्लास्टिक उत्पादित किया जाता है। इसमें से केवल नौ फीसदी प्लास्टिक ही रीसाइकल किया जाता है। यदि इस समस्या पर गंभीरता से गौर न किया गया तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जगह बनाने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा 2040 तक करीब 2.9 करोड़ टन पर पहुंच जाएगी।

एक सर्वे में हुआ खुलासा... डिजिटल लत के खतरे का सामना कर रहे 60 प्रतिशत बच्चे

एक नये सर्वेक्षण से खुलासा हुआ है कि 5-16 वर्ष की आयु के बीच के लगभग 60 प्रतिशत बच्चे संभावित डिजिटल लत का संकेत देने वाले व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

स्मार्ट पैरेंट सॉल्यूशन कंपनी'बाटू टेक' द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के नतीजे 1,000 माता-पिता के नमूना आकार पर आधारित है। सर्वेक्षण का उद्देश्य यह सामने लाना है कि मोबाइल के उपयोग पर अधिक समय खर्च करना किस प्रकार नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करने के साथ ही शारीरिक गतिविधियों में कमी, समाज से दूरी और शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी सहित विभिन्न जोखिम पैदा करता है।

सर्वेक्षण में कहा गया है,''लगभग 60 प्रतिशत बच्चे संभावित डिजिटल लत का संकेत देने वाले

व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और लगभग 85 प्रतिशत माता-पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन सामग्री खपत को प्रबंधित करने में कठिनाई आने की बात स्वीकार करते हैं।

खुलकर सांस ले रहा जम्मू-कश्मीर

विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वार, कुछ परिवारों के फायदे के लिए राज्य को जंजीरों में जकड़ा गया था

मोदी ने कहा कि 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार ही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर की अपनी पहली यात्रा में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 'विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर' कार्यक्रम के दौरान 6,400 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर आज खुलकर सांस ले रहा है। बन्दिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। उन्होंने कहा कि दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया।

मोदी ने कहा कि 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार ही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान

अधिकार भी हैं, समान अवसर भी हैं।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां की झीलों में जगह-जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगो में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि भाजपा का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि जब इरादे नेक हों, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं।

इस साल कर्मचारियों के वेतन औसतन 9.6 फीसदी बढ़ाएंगी भारतीय कंपनियां : रिपोर्ट

वित्तीय सेवा क्षेत्र में 10.1 प्रतिशत की वेतनवृद्धि का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि पेशेवर सेवा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन वेतन 2024 में 10 प्रतिशत बढ़ेगा।

देश में कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में 2024 में औसतन 9.6 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं। यह पिछले साल की वेतन वृद्धि के बराबर है। परामर्श कंपनी ईवाई की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा कि कुल मिलाकर नौकरी छोड़ने की दर पिछले साल 2022 के 21.2 प्रतिशत से घटकर 18.3 प्रतिशत रह गई है। अगले कुछ साल में इसमें और कमी आने की संभावना है। रिपोर्ट कहती है कि ई-कॉमर्स क्षेत्र में 2024 में सबसे अधिक 10.9 प्रतिशत वेतनवृद्धि की उम्मीद है। इसके बाद वित्तीय सेवा क्षेत्र में 10.1 प्रतिशत की वेतनवृद्धि का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि पेशेवर सेवा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन वेतन 2024 में 10 प्रतिशत

बढ़ेगा। यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों की 80 कंपनियों से मिली जानकारी पर आधारित है। इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या औसतन 5,000 से 10,000 के बीच है। इसमें कहा गया है कि भारतीय कंपनियां 2024 में औसतन 9.6 प्रतिशत वेतनवृद्धि देंगी, जो 2023 की वास्तविक वृद्धि के समान है।

पीएम मोदी ने जया किशोरी को दिया बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवॉर्ड, बोले-

लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेकर चले जाना...

पीएम मोदी ने इंटरनेशनल विमेंस डे पर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में यूट्यूब और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवॉर्ड मिला। सोशल मीडिया पर इनोवेशन और कंटेट के जरिए जागरूकता फैला रहे कई अन्य क्रिएटर्स भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किए गए।

पीएम मोदी ने इंटरनेशनल विमेंस डे पर पहले 'नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट से जागरूकता फैला रहे क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने क्रिएटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि यह अवॉर्ड पहली बार आयोजित हो रहे हैं। इससे क्रियेटर्स को मोटिवेशन मिलेगा।

नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड में प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी भी शामिल हुईं। उन्हें बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवॉर्ड मिला है। जया किशोरी ने लोगों में आध्यात्मिक दुनिया की तरफ आधुनिक तरीके से रूचि फैलाने का काम किया है। मंच पर अवॉर्ड लेने पहुंची जया किशोरी को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने उनका परिचय पूछ लिया। इस सवाल पर जया किशोरी ने बताया कि 'मैं कथाकार हूं। श्रीमद भागवतम करती हूं। गीता की बातें करती हूं। मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है और जो बदलाव मुझमें आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर। सबसे बड़ी बात कि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है। मुझे लगता है कि ये सबसे गलत सोच है। क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म

की जरूरत युवाओं को है। अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ-साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूं। तो मुझे लगता है हर कोई जी सकता है।'

इसके बाद पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि 'लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेकर चले जाना।' इस पर जया किशोरी ने कहा कि 'ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद भगवत गीता। जो ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, जो राजा बनने वाला है। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। गीता में भगवान कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो। बस कहा कि अपना धर्म पूरा करो, जहां भी हो।'

उत्तरप्रदेश में जंगल राज, कानून नाम की चीज नहीं बची : प्रियंका गांधी

आरोप है कि पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में पीड़ित बच्चियां-महिलाएं अगर न्याय मांगती हैं तो उनके परिवारों को बर्बाद कर देना नियम बन चुका है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो बच्चियों के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि राज्य में जंगल राज है, जहां कानून नाम की चीज नहीं बची है। उन्होंने यह दावा भी किया कि उत्तर प्रदेश में पीड़ित बच्चियां-महिलाएं अगर न्याय मांगती हैं तो उनके परिवारों को बर्बाद कर देना नियम बन चुका है। प्रियंका गांधी ने

सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, कानपुर में सामूहिक बलात्कार की पीड़ित दो नाबालिग बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। अब उन बच्चियों के पिता ने भी आत्महत्या कर ली है।

आरोप है कि पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में पीड़ित बच्चियां-महिलाएं अगर न्याय मांगती हैं तो उनके परिवारों को बर्बाद कर देना नियम बन चुका है।

उन्नाव, हाथरस से लेकर कानपुर तक- जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार बर्बाद कर दिए गए। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि इस जंगलराज में महिला होना मात्र अपराध हो गया है, जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है।

बीते दशक में बैंकिंग और आर्थिक क्षेत्र में कई सुधार

बदलते चेहरे के साथ तेज विकास की संभावना...

मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बैंकिंग और आर्थिक क्षेत्र में कई सुधार किए, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में आगे भी तीव्र विकास की संभावना है।

वर्ष 1991 से देश में आर्थिक सुधार का शुभारंभ हुआ था, लेकिन इस दिशा में अब तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। 1991 में विदेश व्यापार, कर सुधार, विदेशी निवेश आदि क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अनेक उपाय किए गए, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिली। मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने से पहले, यानी 2013 में वर्तमान मूल्य पर भारत की जीडीपी 18 खरब डॉलर और 2007 में लगभग 10 खरब डॉलर थी। इस तरह, 1947 से ठीक 60 वर्षों बाद भारत की जीडीपी 2007 में 10 खरब डॉलर की हुई। आज रियल जीडीपी के हिसाब से भी भारतीय अर्थव्यवस्था 30 खरब डॉलर की हो गई है। 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि 2019 में, यानी सिर्फ पांच वर्षों के भीतर यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र के माध्यम से यूपीए सरकार के कार्यकाल की नाकामियों और मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को आम जनता के समक्ष रखते हुए बताया कि 2014 से पहले देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मोदी सरकार को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। इसके जवाब में कांग्रेस ने ब्लैक पेपर पेश किया, जिसमें मोदी सरकार की नाकामियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भाजपा लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रही है और इसके कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, भारत की जीडीपी वर्तमान मूल्य पर अभी 37.3 खरब डॉलर की है, जबकि आजादी के समय भारत की जीडीपी 227 अरब डॉलर की थी। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बैंकिंग और आर्थिक क्षेत्र में कई सुधार किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का शुभारंभ, बैंकों का आपस में विलय, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम-स्वनिधि योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) आदि का आगाज।

द इंडियन इकनॉमी : ए रिव्यू रिपोर्ट में मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के सफर को आर्थिक सुधारों के संदर्भ में बहुत ही अहम बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में नॉमिनल जीडीपी के सात प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 7.3 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जताया गया है। यही नहीं, यह संभावना भी जताई गई है कि भारत की जीडीपी 2030 तक सात प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकती है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल ने भी भारत के वित्तीय क्षेत्र में आई मजबूती और सरकार द्वारा किए गए हालिया संरचनात्मक सुधारों की वजह से सरकार के इस दावे की पुष्टि की है। ऐसे में, 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 50 खरब डॉलर और 2030 में 70 खरब डॉलर से भी अधिक का हो जाएगा। पीपीपी के मामले में 2023 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर थे।

अस्सी के दशक में पहली बार, वित्त वर्ष 1989-90 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सूचकांक ने 1,000 के अंक के स्तर को पार किया था। वर्ष 2006 में बीएसई सूचकांक ने 10,000 अंक के स्तर को पार किया। फिर वित्त वर्ष 2014-15 में यह 30,000 अंक के स्तर को और वित्त वर्ष 2018-19 में 40,000 अंक के स्तर को पार किया। वित्त वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 70,000 अंक के स्तर को पार कर गया। निफ्टी सूचकांक भी वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 21,000 अंक के स्तर को पार कर गया।

भारत में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर नियंत्रण में है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आगामी वर्षों में भी मजबूती बनी रहेगी। बेशक जीडीपी के अनुपात में सरकारी कर्ज का प्रतिशत अधिक है, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य कर व गैर-कर राजस्व संग्रह में आ रही तेजी से इसमें आने वाले वर्षों में कुछ कमी आने की संभावना है।

मध्य प्रदेश की वो छह लोकसभा सीटें...

जहां बीजेपी और कांग्रेस में होगा बड़ा घमासान

प्रदेश में लोस चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश की 6 सीटें ऐसी हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा घमासान होगा।

लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा मार्च के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। इससे पहले सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी एक कदम आगे चल रही है। कांग्रेस अभी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। बीजेपी ने 24 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इन सबके बावजूद मध्य प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस को बीजेपी से जोरदार टक्कर मिलेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान यह संकेत मिल गए हैं। बीजेपी की आंधी में भी उन जगहों पर ज्यादा नुकसान कांग्रेस को नहीं हुआ है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उम्मीदवारों की सूची जल्द आ जाएगी। कुछ दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था कि हम लोकसभा की 12-13 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस नेताओं के दावे से इतर विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएं हैं, उससे यह संकेत है कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है। इन जगहों पर कांग्रेस बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दे सकती है। वैसे सीटों की बात करें तो ग्वालियर, रतलाम, धार, बालाघाट, मुरैना और छिंदवाड़ा है। बीजेपी ने इनमें से कुछ लोकसभा सीटों पर अभी उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए हैं। धार, छिंदवाड़ा और बालाघाट सीट के लिए अभी बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। वहीं, कांग्रेस ने अभी किसी सीट पर नाम फाइनल नहीं किए हैं। ग्वालियर, मुरैना और रतलाम सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी दे दिए हैं। इन सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने तैयारी शुरू कर दी है।

रतलाम में हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला : लोकसभा चुनाव 2024 में रतलाम सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने यहां से अनिता नागर सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं। रतलाम जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन पांच में से चार सीटें बीजेपी जीती है। एक सीट बाप के खाते में गया है। हालांकि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत झाबुआ जिला भी आता है। यह आदिवासी बाहुल इलाका है। यहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अगर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी की राह आसान नहीं है।

छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा चैलेंज : छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस का अभेद किला है। मध्यप्रदेश में यह इकलौती सीट है, जहां बीजेपी जीत के लिए तरस रही है। विधानसभा चुनाव में इस बार भी वहां खाता नहीं खुला है। सातों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं, कांग्रेस नेता कमलनाथ कह चुके हैं कि नकुलनाथ ही यहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं।

मुरैना में भी मिलेगी जोरदार टक्कर : मुरैना लोकसभा सीट से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे। उनके इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गया है। इस बार बीजेपी ने यहां से शिवमंगल सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव के दौरान मुरैना लोकसभा सीट के अंदर आने वाले आठ में से पांच सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता के होने के बावजूद बीजेपी को तीन सीटों पर जीत मिली थी।

ग्वालियर में भी नहीं है राह आसान : वहीं, इस बार ग्वालियर में बीजेपी की राह आसान नहीं है। इस बार पार्टी ने भारत सिंह कुशवाह को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव के दौरान यहां भी कांग्रेस ने बीजेपी को तीन सीटों पर शिकस्त दी थी। भारत सिंह कुशवाहा भी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस अगर धाकड़ उम्मीदवार उतारती है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएगी।

धार में भी कांग्रेस का दिखा था दबदबा : धार लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इसी लोकसभा सीट से आते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को यहां पांच सीटों पर जीत मिली थी। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अभी तक यहां उम्मीदवार फाइनल नहीं किए हैं। गौरतलब है कि इन समीकरणों को देखते हुए बीजेपी भी अपनी कमजोरी पर मेहनत कर रही है। लगातार पार्टी के बड़े नेता यहां एक्टिव हैं। साथ ही बूथ को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी ने इस बार 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है।

प्रदेश पर्यटन स्थल... ईको पर्यटन स्थलों पर परोसी जाएगी शराब

50 हजार रुपये में लाइसेंस देगी सरकार

आबकारी विभाग ने एक नया पर्यटन बार लाइसेंस का प्रविधान किया हुआ है जिसमें ईको टूरिज्म बोर्ड की इकाईयों को मात्र 50 हजार रुपये वार्षिक फीस पर यह लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे इन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा।

मध्य प्रदेश के ईको पर्यटन स्थलों पर भी शराब परोसी जाएगी। इसके लिए महज 50 हजार रुपये वार्षिक फीस पर शराब का लाइसेंस दिया जाएगा। यह लाइसेंस पर्यटकों के ठहरने के लिए बनाई गई अस्थाई संरचनाओं जैसे टेंट के लिए भी मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे इन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। इको पर्यटन बोर्ड के प्रदेशभर में 291 से अधिक ईको पर्यटन स्थल हैं। यहां कुछ स्थानों पर शराब की उपलब्धता कराई जाती है। शेष अन्य ईको पर्यटन स्थालों पर भी इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

पर्यटन बार लाइसेंस का प्रविधान : दरअसल, आबकारी विभाग ने एक नया पर्यटन बार लाइसेंस का प्रविधान किया हुआ है जिसमें ईको टूरिज्म बोर्ड की इकाईयों को मात्र 50 हजार रुपये वार्षिक फीस पर यह लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ईको पर्यटन बोर्ड के अंतर्गत वन सर्किल क्षेत्रों में मनोरंजन क्षेत्र 127, वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र 14, बफर एरिया डेस्टीनेशन 33, संरक्षित एरिया डेस्टीनेशन 47, अन्य एरिया डेस्टीनेशन 49 तथा पीपीपी मोड वाला देवास का अर्निका ईको पार्क शामिल है।

ईको पर्यटन स्थलों पर मिट्टी के घरों का निर्माण कराया जा रहा है। यहां चूल्हे पर ही भोजन पकाया जाता है। पर्यटकों को जंगल की अनुभूमि कराने के उद्देश्य से यह प्रयोग किया जा रहा है। वहीं मकानों के निर्माण में बांस और घास का भी प्रयोग किया गया है।

हादसे के शिकार व्यक्ति के परिजनों को ₹1.35 करोड़ के मुआवजे के आदेश...

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 48 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 1.35 करोड़ रुपये का मुआवजा देना का आदेश दिया है। एमएसीटी के अध्यक्ष एसबी अग्रवाल ने 12 फरवरी को पारित आदेश में कहा कि दोषी बस का मालिक और उसकी बीमा कंपनी संयुक्त रूप से मुआवजे की राशि का भुगतान याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ करें। आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गयी। ग्यारह नवंबर 2018 को महाराष्ट्र के सिन्नर-शिरडी रोड पर एक बस की पीड़ित के वाहन से टक्कर हो जाने से पीड़ित, ठाणे के मीरा रोड इलाके के निवासी एग्नेल इयपुन्नी चक्रमाकिल और कार में सवार चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी।

याचिकाकर्ता एग्नेल की 52 वर्षीय पत्नी और 31 साल के बेटे ने तर्क दिया कि बस चालक वाहन को लापरवाही

से चला रहा था जिससे भीषण टक्कर हुई। उन्होंने एग्नेल की मौत के लिए 2.70 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। बस का मालिक न्यायाधिकरण के सामने पेश नहीं हुआ, इसलिए मामले में उसके खिलाफ एकपक्षीय फैसला सुनाया गया। न्यायाधिकरण ने एग्नेल की एक लाख रुपये की मासिक आय और भविष्य की आय की संभावनाओं के लिए 30 प्रतिशत अतिरिक्त रकम को ध्यान में रखते हुए दावे की गणना की। एमएसीटी ने मृतक की उम्र के आधार पर मुआवजे की गणना की जिससे मुआवजे का आंकड़ा 1,35,90,052 रुपये पर पहुंच गया, जिसमें आय, संपत्ति, सहायता संघ और अंतिम संस्कार का खर्च शामिल हैं। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि पीड़ित की पत्नी के लिए एक करोड़ रुपये और उसके बेटे के लिए पांच लाख रुपये सावधि जमा में रखे जाएं और शेष एवं अर्जित ब्याज का भुगतान महिला को खाते में भुगतान किये जाने वाले चेक के माध्यम से किया जाए।

सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे में घाटे का सौदा करने के लिए...

मजबूर कांग्रेस...

कभी देश में एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर घाटे का सौदा करने को मजबूर हो गई है। कांग्रेस की यह हालत पिछले लोकसभा चुनाव में और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद हुई है। कमजोर होती कांग्रेस से रिक्त हुआ राजनीतिक स्थान क्षेत्रीय दल ले रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि यदि राजनीति में टिकना है तो क्षेत्रीय दलों के सामने झुकना है। कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके करीब 70 सीटों की कुर्बानी दे चुकी है। इन सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से कांग्रेस मात्र 52 सीटें जीतने में कामयाब हो सकी। जिस तरह कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर रही है, उससे आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े दल के तौर पर उभर कर आने पर ब्रेक लग सकता है। ऐसी हालत में केंद्र में यदि गैरभाजपा गठबंधन बहुमत में आता भी है तो कांग्रेस के लिए कप्तान की भूमिका निभा पाना मुश्किल होगा।

हालांकि विगत विधानसभा चुनाव को यदि लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी मानें तो विपक्षी दलों की केंद्र में सरकार बनाने के संभावना क्षीण है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली के अलावा हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में भी गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी 46 में से सात सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गोवा और चंडीगढ़ के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने की तैयारी की थी, लेकिन गठबंधन के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। गोवा में एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान करने के बाद आम आदमी पार्टी ने दोनों सीटें कांग्रेस को दी हैं। दिल्ली में भी पहले आम आदमी पार्टी ने छह सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन बाद में चार सीटों पर ही समझौता कर लिया। दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति पर समझौता करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी सात में से चार सीटों- पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली पर चुनाव लड़ेगी। शेष तीन- उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और चांदनी चौक संसदीय सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी सात सीटों पर जीत दर्ज की थी। लगातार दो बार लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के प्रत्याशी एक भी सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुए। गुजरात में 26 में से दो सीटें अनुसूचित जाति और चार सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आम आदमी पार्टी दो और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की कमजोर राजनीतिक हालत का फायदा उठाने से गठबंधन का कोई भी दल नहीं चूक रहा है। हर दल जितना हो सके कांग्रेस की बांह मरोड़ने में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी के तीखे तेवर दिखाने के बाद कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। कांग्रेस अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से डील कर चुकी है। पार्टी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के बीच आठ सीटों पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है, जिसके बीच गतिरोध बना हुआ है। पश्चिम बंगाल भी कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है। तृणमूल सभी

नागपुर मॉडल को फॉलो करेगा इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट, सिंहस्थ में उज्जैन तक चलेगी...

पिलर पेंटिंग पर खर्च किए जाएंगे 9 करोड़ रुपए

मेट्रो प्रोजेक्ट के विकास में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार अब नागपुर मॉडल को फॉलो करके यहां मेट्रो के मीडिअन को खूबसूरत बनाने का काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसमें 7 किमी तक के पिलर पर पेंटिंग की जाएगी। जानकारी के अनुसार इसपर लगभग 9 करोड़ रुपये का खर्च होगा। दरअसल आपको बता दें की इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के काम तेजी से चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब पिलर और ट्रैक का निर्माण भी पूरा चुका है। बता दें मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पिलर पेंटिंग का जिम्मा नगर निगम को दिया है। जिसके बाद निगम अधिकारियों ने दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, भोपाल जैसे शहरों के मॉडल को पूरा स्टडी किया है और इसके बाद इंदौर मेट्रो को नागपुर मॉडल पर बनाने का फाइनल किया गया है। हालांकि नागपुर मॉडल की बात की जाए तो इसमें सड़क के दोनों तरफ घनी हरियाली है, और इसके लिए वहां रेलिंग लगाई गई है लेकिन इंदौर में रेलिंग की जरूरत नहीं है।

जानकारी के मुताबिक, लवकुश चौराहा पर ब्रिज बनाया जा रहा है। जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दरअसल ब्रिज के दो हिस्से होने वाले है जिसके बीच में मेट्रो चलेगी। जानकारी दे दें की एक ब्रिज के एक तरफ सुपर कॉरिडोर की तरफ और दूसरी एमआर-10

हिस्से में मेट्रो संचालित होगी। जिसका निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। दरअसल दो ब्रिज बनाने का मुख्य कारण ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना भी है। वहीं प्रदेश सरकार ने 2028 तक इसे उज्जैन तक चलाने का भी मन बना लिया है जिसके लिए सर्वे सहित अन्य कागजी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने उज्जैन ही नहीं महू और पीथमपुर तक भी मेट्रो चलाने पर काम शुरू कर दिया है।

200 करोड़ का जेट प्लेन लेगी प्रदेश सरकार, हेलिकाप्टर के लिए भी ईओआइ की जारी

मध्य प्रदेश सरकार दो साल से जेट प्लेन खरीदने के लिए प्रयास कर रही है लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रविधान भी रखा था लेकिन कुछ नए प्रविधान के कारण मामला अटक गया। अब पूर्व निविदा की गई है, जिसमें कुछ कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं, जिन पर निर्णय लिया जाना है। वहीं, हेलिकाप्टर लेने के लिए एक्सप्रेशन आफ इंट्रेस्ट (इओआइ) जारी की गई है। कंपनियों द्वारा आपूर्ति की रूचि दिखाने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

शिवराज सरकार में जेट प्लेन खरीदने के लिए बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया था। अमेरिका की टेक्स्ट्रान एविएशन कंपनी से बात भी हुई थी और वह 208 करोड़ रुपये में जेट प्लेन देने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के प्रभावी हो जाने से प्रक्रिया रुक गई थी। मोहन सरकार में नए सिरे से कवायद हुई और पूर्व निविदा जारी की गई। विमानन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ कंपनियों ने जेट प्लेन देने के प्रस्ताव दिए हैं। इनका परीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जाएगी। जेट प्लेन ऐसा लिया जा रहा है जिसमें दो पायलट के अलावा आठ से दस यात्रियों को ले जाने

की सुविधा होगी। प्लेन निरंतर एक हजार की बजाए दो हजार नोटीकल माइल उड़ान भरने की क्षमता हो। रात में भी टैकआफ और लैंड कर सके। पांच हजार फीट की हवाई पट्टी पर भी उतर सके। इसी तरह हेलिकाप्टर भी आठ से दस यात्रियों को ले जाने सहित रात में टैकआफ और लैंड कर सके।

न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह प्रदेश के नए लोकायुक्त...

राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ

राज्य शासन द्वारा न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्यप्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने रविवार देर शाम राजभवन में आयोजित गरिमामय समारोह में न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्यप्रदेश के नए लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने नवनियुक्त लोकायुक्त जस्टिस सिंह को पुष्पगुच्छ भेंटकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वर्तमान न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता का कार्यकाल पिछले साल 17 अक्टूबर को ही पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने से उनका कार्यकाल स्वतः ही बढ़ गया था। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद ही प्रदेश को नया लोकायुक्त मिलेगा, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले पूर्व न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को लोकायुक्त बनाया गया है। उन्होंने न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। राजभवन के सांदीपनि सभागार में रविवार देर शाम आयोजित गरिमामय समारोह में राज्यपाल पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन मुख्य सचिव वीरा राणा ने किया। शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद वीडी शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला, विभिन्न आयोगों के पदाधिकारी, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, जन प्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने उठाया था सवाल : बता दें कि मध्यप्रदेश में नए लोकायुक्त की नियुक्ति पर कांग्रेस ने सवाल उठाया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लोकायुक्त की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा -मुझे जानकारी दिए बिना लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। नियम के अनुसार मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष से नियुक्ति से पहले परामर्श जरूरी है। नियुक्ति को रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कहा कि नियुक्ति रद्द नहीं की गई तो न्यायालय का शरण लूंगा। सरकार द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जो नियम फॉलो किया गया वह अवैध है। तत्काल नियुक्ति को रद्द कर शपथ ग्रहण के समारोह को भी निरस्त किया जाए।

प्रदेश में साल 2027 से मंडला, खजुराहो, धार और बालाघाट में शुरू हो जाएंगे आयुर्वेद कालेज

मेडिकल कालेजों की तरह प्रदेश सरकार अब आयुर्वेद कालेज की संख्या भी बढ़ाने जा रही है। मंडला, खजुराहो, धार और बालाघाट में कालेज शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव कर चुके हैं। इसी वर्ष इन कालेजों का निर्माण शुरू होगा। आयुष संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2027-28 से इन कालेजों में प्रवेश शुरू करने की तैयारी है। इनके अतिरिक्त सागर, शुजालपुर, झाबुआ, शहडोल, नर्मदापुरम, श्योपुर और मुरैना में भी कालेज शुरू किए जाएंगे। जिला अस्पतालों का 30 बिस्तर के अस्पताल में उन्नयन कर शुरू में कालेज संचालित किए जाएंगे। बाद में कालेजों का अलग से अस्पताल बनाया जाएगा। इन कालेजों में कुछ में 60 और कुछ में 100 सीटें रहेंगी। नए कालेज शुरू करने के लिए आयुक्त आयुष सोनाली पोंछे वायंगणकर ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर सुगम स्थान पर पांच एकड़ भूमि आंवटित करने के लिए कहा है। प्रदेश में वर्तमान में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, बुरहानपुर और रीवा मिलाकर छह कालेज हैं। सभी जगह मिलाकर 600 सीटें हैं। राजगढ़ जिला अस्पताल में खतरे में पड़ी बच्चों की जान, पीआइसीयू वार्ड की लाइट हुई बंद, जनरेटर भी नहीं चलाराजगढ़ जिला अस्पताल में खतरे में पड़ी बच्चों की जान, पीआइसीयू वार्ड की लाइट हुई बंद, जनरेटर भी नहीं चला।

11 और कालेज शुरू होने से 600 से 1100 सीटें बढ़ जाएंगी। इससे प्रदेश को डाक्टर तो मिलेंगे ही, कालेजों को फैकल्टी मिल सकेंगे। आगे चलकर एमडी-एमएस और शोध को बढ़ावा मिलेगा। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा.राकेश पाण्डेय ने कहा कि नए कालेज खुलने से जहां बीएएमएस की 1100 सीटें बढ़ जाएंगी, वहीं एमडी-एमएस की सीटें भी बढ़ सकेंगी। प्रदेश में अभी सात सरकारी आयुर्वेदिक कालेज हैं। इनमें आखिरी कालेज वर्ष 1995 में भोपाल में पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कालेज खुला था। यानी बीते 28 वर्ष से प्रदेश में एक भी आयुर्वेद कालेज नहीं खुला।

तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध

अदृश्य दुश्मन पर नजर रखने के लिए हुई हैं कुछ सराहनीय पहल

इंटरनेट की ताकत ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। यही वजह है कि आज साइबर अपराध दुनिया भर के देशों के लिए चुनौती बन चुके हैं। भारत में चक्षु और डीआईपी जैसी पहलें सराहनीय हैं, लेकिन साइबर अपराधी जिस तरह नित-नए तरीके लेकर आ रहे हैं, लोगों को भी जागरूक होना होगा।

भारत बड़े स्तर पर साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी के हमलों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तो साइबर अपराध के मामले बड़े पैमाने पर बढ़े हैं। दरअसल, कोविड-19 का दौर साइबर अपराध के लिए स्वर्ण युग के रूप में आया। लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखकर यही लगता है कि यह आगामी कई दशकों तक हमारे साथ रहने वाला है। आज हम नित-नए प्रकार के साइबर अपराध के मामले देख रहे हैं।

दुनिया भर के देशों के लिए साइबर अपराध बड़ी चुनौती बन चुके हैं। सच तो यह है कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। इंटरनेट ने साइबर अपराधियों को उनके अपराध का पूरा ताना-बाना बुनने में मदद की है। ऐसे में, साइबर अपराधियों की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति राष्ट्रीय सरकारों के लिए मुसीबत बन गई है। जबकि, सरकारें साइबर अपराध को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय कानून अपना रही हैं।

दरअसल, साइबर अपराधी जल्द पैसा कमाने के सारे हथकंडे जानते हैं। अपराधियों को पता होता है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को विश्वास में लेकर कैसे आसानी से उन्हें अपना शिकार बनाया जा सकता है और पैसा कमाया जा सकता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी आज सबसे बड़े अपराधों में एक हो गई है। आए-दिन हमारे आसपास का कोई न कोई व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनता दिखता है। अनुमान है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाला हर तीसरा व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी से पीड़ित है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में आज ज्यादा से ज्यादा लोग बिना किसी प्रशिक्षण के इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। और, जब व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ता है, तो तमाम सूचनाओं और चुनौतियों के गहरे सागर में गोते लगाता है। भारत में साइबर धोखाधड़ी और अपराध एक तरह से कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है और यह तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में पहचान की चोरी, फिशिंग और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी भारत में सबसे प्रचलित तीन साइबर अपराध हैं। लेकिन समस्या यह है कि अपने देश में साइबर अपराध के मामलों में सजा का अनुपात एक फीसदी से भी कम है। वर्तमान साइबर कानून बढ़ते हुए साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में साइबर धोखाधड़ियों से निपटने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है। व्यावहारिक रूप से सभी ऑनलाइन वित्तीय

धोखाधड़ी में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 के तहत पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन इसके बावजूद हम साइबर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी संरचना और दूरसंचार नेटवर्क का दुरुपयोग होता देखते हैं।

भारत सरकार साइबर अपराध और धोखाधड़ी को लेकर अत्यधिक चिंतित है। यही कारण है कि सरकार ने कुछ समय पहले 'संचार साथी' पोर्टल लॉन्च किया था। नागरिकों के हित में यह पोर्टल मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए दूरसंचार विभाग की बड़ी पहल है। संचार साथी के आने के बाद अब लोगों को पता चल जाता है कि उनके नाम पर कितने सिम कार्ड पंजीकृत हैं।

इसके अलावा, हाल ही में भारत सरकार ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है। लोग इस पोर्टल पर साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप आदि माध्यमों से होने वाली किसी भी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चक्षु ऑनलाइन धोखाधड़ी से लड़ने के लिए लोगों को शक्तिशाली बनाता है। इससे पहले व्यवस्था थी कि जब कोई साइबर अपराध का शिकार होता था, तो वह उसकी शिकायत कर सकता था। हालांकि नई सरकारी पहलों ने मौजूदा ढांचे के दायरे को बढ़ाया है।

चक्षु का उद्देश्य धोखाधड़ी वाले संदेशों और संचारों को उजागर करना और उनका मिलान करना है। यह अंतिम पंक्ति के उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाता है। चक्षु साइबर अपराध से निपटने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह सरकार को उन सभी संदिग्ध संदेशों और संचारों का भंडार बनाने की अनुमति देगा, जो साइबर अपराधियों द्वारा निर्दोष उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के लिए तेजी से उपयोग किए जा रहे हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि चक्षु पोर्टल न केवल उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अपने अनुभव भी साझा कर सकेंगे। साथ ही लोग साइबर अपराध के नए तरीकों से बचने के लिए संवेदनशील बनेंगे। सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए चक्षु पर संदिग्ध संदेशों को प्रकाशित कर सकती है। इस तरह की जागरूकता से साइबर अपराध के विरुद्ध लड़ने की क्षमता का निर्माण होगा। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) भी लॉन्च किया है, जो दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करना है, ताकि सरकारी तंत्र साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ने के लिए एकीकृत ढंग से काम कर सके। चक्षु और डीआईपी की शुरुआत साइबर धोखाधड़ी और अपराधों के बढ़ते खतरे से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। चक्षु को तैयार करने के लिए सरकार की तारीफ करनी चाहिए।

इसके अलावा निरंतर जागरूकता की भी जरूरत होगी, ताकि भारतीय डिजिटल उपयोगकर्ताओं को आगे भी सशक्त बनाया जा सके। हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने के नए-नए तरीके आजमाएंगे। साथ ही सरकार को भी साइबर अपराध की नई-नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। कानूनी ढांचे को अपडेट करने के साथ ही साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को भी बढ़ाना होगा। साथ ही प्रत्येक हितधारक को साइबर अपराध से लड़ने के लिए अपना-अपना योगदान देना होगा।

इन बलों की निगरानी में रहेंगी 55 लाख ईवीएम, स्ट्रांग रूम की हिफाजत करेंगे केंद्रीय अर्धसैनिक बल

भारतीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक, चुनाव संपन्न कराने की पूर्ण प्रक्रिया की जिम्मेदारी केंद्रीय बलों और स्थानीय पुलिस के पास रहेगी। केंद्रीय बल, स्थानीय पुलिस की मदद के लिए तैयार रहेंगे। जहां कहीं भी चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने की आशंका नजर आएगी, वहां पर तुरंत केंद्रीय बलों को रवाना कर दिया जाएगा...

देश में लोकसभा की 543 सीटों के लिए सात चरणों में चुनाव संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और एक जून को सातवें चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती चार जून को होगी। लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी बाधा के चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए चार लाख वाहनों का इस्तेमाल होगा। खास बात यह है कि पोलिंग स्टेशन और उसके रूट का मुआयना करने के लिए केंद्रीय बल एवं स्टेट आर्म्ड पुलिस, कई दिन पहले ही संबंधित क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। इस चुनाव में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीएपीएफ' और स्टेट आर्म्ड पुलिस 'एसएपी' को दी गई है। इतना ही नहीं, वीपीपैट और स्ट्रांग रूम की हिफाजत का दायित्व भी उक्त दोनों बलों के पास रहेगा। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक, चुनाव संपन्न कराने की पूर्ण प्रक्रिया की जिम्मेदारी केंद्रीय बलों और स्थानीय पुलिस के पास रहेगी। केंद्रीय बल, स्थानीय पुलिस की मदद के लिए तैयार रहेंगे। जहां कहीं भी चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने की आशंका नजर आएगी, वहां पर तुरंत केंद्रीय बलों को रवाना कर दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को विज्ञान भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा, यह चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि देश में लोकसभा चुनाव, पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों।

इसके लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। लोगों को किसी तरह का कोई भय न हो, वे निष्पक्ष तरीके से मतदान करें, इसके लिए केंद्रीय बलों को चुनाव से कई दिन पहले ही उनके क्षेत्रों में तैनात कर दिया जाएगा। समाज के कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं दूसरे समुदायों का भरोसा, निर्वाचन प्रणाली में बना रहे, इसके लिए केंद्रीय बल तैनात किए जा रहे हैं। ये बल, लोगों के बीच जाकर ऐसा माहौल तैयार करते हैं, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की प्रेरणा मिले। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर चुनाव अधिकारी की सलाह से केंद्रीय बल, मार्च कर सकते हैं।

पोलिंग स्टेशन और वहां पर वोट डालने के लिए आने वाले वोटरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, केंद्रीय बलों एवं एसएपी की रहेगी। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम, जहां पर ईवीएम/वीवीपैट रखे जाएंगे, उसकी पूर्ण सुरक्षा के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहां पर शिफ्टवाइज ड्यूटी दी जाएगी। 'सीएपीएफ' और 'एसएपी' के जवान, एक पल के लिए भी स्ट्रांग रूम से इधर-उधर नहीं होंगे। मतदान केंद्र एवं स्ट्रांग रूम, यहां पर कितनी संख्या में केंद्रीय बल/एसएपी तैनात होंगे, यह निर्णय चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर तालमेल रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने सीईओ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। इस कमेटी में स्टेट पुलिस नोडल अफसर और स्टेट सीएपीएफ कोआर्डिनेटर भी शामिल होंगे। ये संयुक्त रूप से स्टेट डेप्लॉयमेंट प्लान तैयार करेंगे।

प्रदेश में कांग्रेस के शीर्ष नेता लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं :मुख्यमंत्री

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राज्य की 29 लोकसभा सीट में से किसी पर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं और कहा कि लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालेविपक्षी दल को खारिज कर देंगे।

सीधी सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार राजेश मिश्रा लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के दिन नामांकन पत्र दाखिल करने वाले मध्य प्रदेश के पहले उम्मीदवार बन गये हैं। यादव ने एक आमसभा को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हैं लेकिन उनमें से कोई भी 29 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश की छह सीट पर मतदान होगा।

यादव ने कहा, कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं, जबकि भाजपा के सीधी उम्मीदवार राजेश मिश्रा अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले राज्य के पहले उम्मीदवार बन गए हैं।'' जनसभा को संबोधित करने से पहले मुख्यमंत्री और मिश्रा ने एक रोड शो में हिस्सा लिया। बाद में मुख्यमंत्री भाजपा उम्मीदवार के साथ सीधी जिलाधिकारी कार्यालय गए जहां मिश्रा ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। विपक्षी कांग्रेस ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (सीडब्ल्यूसी) सदस्य कमलेश्वर पटेल को सीधी सीट से मिश्रा के खिलाफ मैदान में उतारा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने छिंदवाड़ा को छोड़कर 29 में से 28 निर्वाचन क्षेत्रों पर कब्जा करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस का लगभग सफाया कर दिया था। , छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नकुल नाथ

ने जीत हासिल की थी।

सभा को संबोधित करते हुए यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री (दिवंगत) अटल बिहारी वाजपेयी की उनके नेतृत्व कौशल के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा, '' अटलजी ने विपक्ष में रहते हुए पांच प्रधानमंत्रियों का सामना किया, लेकिन वह कभी नहीं डरे। उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया।''

यादव ने दावा किया कि राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' मध्य प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं डाल पाई। उन्होंने कहा, '' कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और बाद में अयोध्या मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को खारिज कर दिया था। अब लोग आपके उम्मीदवारों को खारिज करके आपको (कांग्रेस) सबक सिखाएंगे। यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पीएम 'श्री एयर एम्बुलेंस सेवा' शुरू की है। कांग्रेस ने अब तक मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है जहां से उसने नकुल नाथ को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

अब मप्र सरकार देगी छह मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन व एमआरआइ की सुविधा

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में रोगियों को सीटी स्कैन और एमआरआई जांच के शुल्क में राहत मिलने वाली है। मप्र सरकार खुद यहां दोनों सुविधाएं शुरू कर रही है। अभी निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) से यह सुविधा मिल रही है। इस कारण गैर आयुष्मान रोगियों को शुल्क देना पड़ रहा है। हालांकि, पीपीपी में शुल्क निजी अस्पतालों की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत ही है। सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध होने पर दरें और कम हो जाएंगी।

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने विद्यार्थियों की क्लीनिकल पढ़ाई के उद्देश्य से खुद की सीटी स्कैन और एमआरआइ मशीन लगाने के लिए कहा है। अभी मशीन निजी निवेशक की होती है, इसलिए एमबीबीएस और एमडी-एमएस के विद्यार्थियों को सीखने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता है। हालांकि, सीटी स्कैन और

एमआरआई दोनों की जांच रिपोर्ट तैयार करने का काम रेडियो डायग्नोसिस विभाग के फैकल्टी और विद्यार्थी ही कर रहे हैं। सरकार मशीन लगाती है तो दोनों सुविधाओं की निरंतरता भी बनी रहेगी। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि सीटी स्कैन और एमआरआइ की सुविधा शुरू करने के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मशीनें स्थापित करने में लगभग चार महीने लग जाएंगे, तब तक पीपीपी से जांच होती रहेगी।

प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं पारदर्शी मतदान के लिए पुलिस की माकूल तैयारियां

राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश के 25 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आगामी 19 अप्रेल व 26 अप्रेल को दो चरणों में होने वाले चुनावों में स्वतंत्र, निष्पक्ष,भयमुक्त एवं पारदर्शी मतदान कराने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे है। आमजन के बीच पारदर्शी तरीके से मतदान को लेकर विश्वास कायम करने के लिए सभी जिलों और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़, लाइसेंसी हथियार जमा कराने, अवैध हथियारों एवं मादक पदार्थों की जप्ती के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में फलैग मार्च भी किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसकी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था श्री विशाल बंसल ने बताया कि लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा पिछले दो महीनों से लगातार तैयारी की जा रही है। गत 7 मार्च को राजस्थान पुलिस को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 25 कंपनी उपलब्ध कराई गई है, इन सभी कम्पनीज को समस्त 25 लोकसभा क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। जो सभी जिलों में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च कर गरीब और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के बीच निडरता के साथ अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए माहौल तैयार कर रही है। राजस्थान पुलिस की धरातल पर यह एक्सरसाइज सभी वर्गों के बीच यह विश्वास पैदा कर रही है कि राजस्थान में शांतिपूर्ण, भय मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जाएगा।

आपराधिक तत्वों पर शिकंजा : श्री बंसल ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से योजनाबद्ध कार्यवाही करते हुए प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन्हें पाबंद करवाया जा रहा है, जो मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते है। जिलों में पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों पर निरंतर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसकी प्रतिदिन

रिपोर्ट ली जा रही है। उन्होंने बताया कि जिलों में अवैध हथियार, मादक पदार्थ एवं शराब तस्करों के मूवमेंट पर निगरानी रखकर उनके सभी सम्भावित रुट एवं चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है और जिलों में पुलिस द्वारा उनकी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई निरंतर जारी है। इसके साथ राजस्थान पुलिस द्वारा ऐसे तस्करों को गिरफ्तार कर हथियार, मादक पदार्थ एवं अवैध शराब को भी जप्त किया जा रहा है। सभी लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया में सम्भावित बाधक आपराधिक व असामाजिक तत्वों को सूचीबद्ध कर उनके विरुद्ध उचित विधिक कार्यवाही भी की जा रही है।

पड़ौसी राज्यों की पुलिस से समन्वय

एडीजी श्री बंसल ने बताया कि प्रदेश के सभी पड़ौसी राज्यों से लगने वाली अंतरराज्यीय सीमा पर चैक पोस्ट स्थापित किये गए हैं। इन पर अवैध सामग्री एवं अवांछनीय व्यक्तियों के राज्य में प्रवेश को रोकने के लिए निगरानी रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त पड़ौसी राज्यो की पुलिस के साथ सतत समन्वय ओर उनके साथ जिला पुलिस टीमों की मीटिंग के जरिए एक दूसरे के वांछित अपराधियों की सूची का आदान प्रदान करते हुए उनकी धरपकड़ जारी है।

अब तक 75 प्रतिशत लाइसेंसी हथियार जमा—

श्री बंसल ने बताया कि लोकसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लगते ही राजस्थान पुलिस द्वारा लाइसेंस हथियार धारकों को अपने हथियार पुलिस थानों या डीलर के पास जमा कराने के लिए पाबंद किया गया है। इसके अंतर्गत करीब 75 प्रतिशत हथियार अब तक जमा किए जा चुके हैं, बाकी हथियारों को भी जमा करने की कार्रवाई जारी है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने किया जनाना अस्पताल का निरीक्षण कहा - अव्यवस्थाएं बर्दाश्त नहीं...

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने शनिवार को जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में पाई गई अव्यवस्थाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सुधार करने तथा संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए।

श्रीमती सिंह ने तकनीकी कारणों से अस्पताल में कुछ समय से बंद रात्रिकालीन ऑपरेशन थियेटर को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में रोगियों की संख्या के अनुरूप आईसीयू बैड्स की आवश्यकता का आकलन कर आईसीयू के विस्तार की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने कहा कि जांच एवं उपचार में रोगियों को किसी तरह की परेशानी एवं विलंब नहीं हो, इसके लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों एवं जांच मशीनों का नियमित मेंटीनेंस सुनिश्चित करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अस्पताल में शौचालयों एवं साफ-सफाई की व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसमें अतिशीघ्र सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में साफ-सफाई के लिए क्यूआर कोड सिस्टम शीघ्र शुरू किया जाए। मरम्मत, रंग-रोगन सहित अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं इलेक्ट्रिक कार्य आरएमआरएस में उपलब्ध फण्ड के माध्यम से शीघ्र कराए जाएं। अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था में सुधार किया जाए। श्रीमती सिंह ने ओपीडी रजिस्टेशन काउंटर, जांच लैब, आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर, लेबर रूम, दवा वितरण केंद्र, पोस्ट नेटल वार्ड, जननी वार्ड, गायनी वार्ड, ब्लड बैंक सहित समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया और इनको बेहतर बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर भी चैक किए और कार्मिकों की उपस्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली। साथ ही, अस्पताल में चल रहे सिविल कार्यों को समय पर पूरा करवाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान रोगियों, परिजनों, चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों सहित अन्य कार्मिकों से संवाद कर अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा, अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. भारती मल्होत्रा, जनाना अस्पताल की अधीक्षक डॉ. कुसुमलता मीणा, उप निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉ. वंदना शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

4 चरणों में होंगे चुनाव

बुजुर्ग व दिव्यांगों के वोट लेने घर-घर जाएगा आयोग

मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चार चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज निर्वाचन सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि एमपी में चार चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। एमपी में 5 करोड 64 लाख 76110 वोटर अगले 5 सालो के लिए अपना सांसद चुनेंगे। एमपी में 85 वर्ष से से ऊपर के कुल 289503 मतदाता है जबकि 579130 दिव्यांग मतदाता दर्ज है जिनको घर बैठे मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदान केंदों पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी,वही EVM मशीन परिवहन वाली सभी गाडियों में जीपीएस लगाया जाएगा।

एमपी के छिंदवाड़ा में सबसे कम पॉलिंग बूथः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि राज्य में सबसे कम छिंदवाड़ा में 1934 मतदान केंद्र, जबकि सबसे ज्यादा मंडला में 2614 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।सबसे कम मतदाता भी छिंदवाड़ा में 1632074 दर्ज है। वही सबसे अधिकतम इंदौर में 2513424 मतदाता सूची में शामिल है। उन्होंने बताया कि एमपी में कुल 64523 कुल मतदान केंद्र और 1500 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जा रहे है। चुनाव में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजन ने बताया कि एमपी में 284503 लाइसेंस हथियार है जिसमे से 125000 हथियार जमा हुए 152 अवैध हथियार जब्त किए गए, पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए साढ़े 5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है।

तस्करी रोकने पूरे प्रदेश में 500 स्थानों पर नाकाबंदी : चुनाव के मौके पर होने वाली शराब और पैसों की तस्करी सहित अन्य गतिविधियों की रोकथाम के लिए भी निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी मजबूत की है। एमपी के 500 से ज्यादा नाकों पर चेकिंग जारी है। निर्वाचन विभाग की टीम दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के साथ ही जिलों की सीमा पर बने नाकों पर भी सघन चेकिंग कर रही है। राजन ने बताया कि गर्मी के हिसाब से छाया और शुद्ध जल की सुविधाएं केन्द्र पर दी जाएगी। शिकायतों के निराकरण के लिए जिला और राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल एमपी में 8000 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में इन संवेदनशील केंद्र की संख्या 16000 थी। अनुपम राजन ने संकेत दिए हैं कि उम्मीदवार के हिसाब से संवेदनशील बूथों की संख्या बढ़ सकती है।

हर सीट पर पांच लाख युवा मतदाता बनेंगे गेम चेंजर

देश की 543 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम तय कर दिया है। चुनाव का ऐलान होते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दुनिया की सर्वाधिक आबादी और सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले भारत देश की सरकार युवाओं की मुट्ठी में होगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भी युवा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दरअसल यह स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि प्रदेश में 1 करोड़ 52 लाख से अधिक युवा मतदाता है, जिनकी उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच है। अगर उम्र को बढ़ा दिया जाए तो 18 वर्ष से 39 वर्ष तक की उम्र के मतदाताओं की संख्या बढ़कर 3 करोड़ पार पहुंच जाती है। यह आंकड़ा कुल मतदाताओं का 50 फीसदी से भी अधिक है। अगर इन मतदाताओं को सभी 29 लोकसभा सीटों की बराबर अनुपात में बांट दिया जाए तो एक लोकसभा सीट में इन युवा मतदाताओं की संख्या लगभग 5 लग 24 हजार 173 होगी। यह संख्या चुनाव जीतने और हारने के लिए बहुत बड़ा गणित है। यह संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया जाती है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटों में जीत हार का अंतर भी 50 हजार से 1 लाख के बीच रहा है। ऐसे में अगर युवा मतदाता जी भी दल की ओर आकर्षित होंगे, उसका चुनाव जीतना निश्चित है। यही कारण है कि सत्ता रूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं को रिझाने में जुटे हुए हैं।

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का मुफ्त में होगा 1.50 लाख का इलाज...

देश में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के अनुसार देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लापरवाही से गाड़ी चलाने, यातायात नियमों के उल्लंघन, गाड़ी चलाने के बारे में जानकारी की कमी के कारण जहां हर दिन सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, वहीं हजारों लोग घायल हो जाते हैं। इनमें से कुछ घायलों को समय पर इलाज न मिलने के कारण अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और लोगों की जान को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया है। कैशलेस इलाज : सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सुरक्षा के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इससे पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सरकार इसे कैशलेस ट्रीटमेंट के तौर पर लेकर आई है। इसकी माध्यम से घायलों को बिना एक भी रुपया खर्च किए इलाज मिल सकेगा। इस योजना के तहत सड़क हादसे के पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। फिलहाल ये स्कीम अभी पायलट प्रोग्राम के तौर पर केवल चंडीगढ़ में लागू की गई है।

इससे आर्थिक रुप से असमर्थ लोगों को आपातकालीन इलाज कराने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत भारत के किसी भी नागरिक को दुर्घटना की स्थिति में तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और उसे 1.5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा। पीड़ित को

इसके तहत 7 दिनों तक कैशलेस इलाज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अस्पताल संबंधित व्यक्ति को दिए गए इलाज के दस्तावेज सीधे सरकार को सौंप सकते हैं और इलाज के पैसे का दावा कर सकती हैं। पायलट प्रोजेक्ट शुरुः केंद्र की ओर से यह योजना अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही शुरू की गई है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंडीगढ़ में लागू किया गया है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो क्रेंद सरकार पूरे देश में इसके विस्तारीकरण पर काम करेगी।

अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो देशभर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या को कम किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में देशभर में कुल 4.61 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इन हादसों में 1.68 लाख लोगों की जान चली गई और 4.43 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्र को उम्मीद है कि अगर यह योजना लागू होती है तो दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता मिलेगी और उनकी जान बचाई जा सकेगी।

चिंताजनक : वैज्ञानिकों का खुलासा, प्लास्टिक में 16 हजार से अधिक रसायन, इसमें चार हजार 200 सबसे खतरनाक

नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल के सहयोग से तैयार की गई स्टेट ऑफ द साइंस ऑन प्लास्टिक केमिकल्स नामक रिपोर्ट के मुताबिक, जितने भी तरह के प्लास्टिक का अध्ययन किया गया है वे सभी हानिकारक रसायन छोड़ते हैं। कभी बेहद उपयोगी समझा जाने वाला प्लास्टिक आज दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। प्लास्टिक में 16,325 रसायन मौजूद हैं। इनमें 26 फीसदी यानी 4,200 रसायन इन्सानों और पर्यावरण दोनों के लिए भारी नुकसानदेह हैं। यूरोप के वैज्ञानिकों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने प्लास्टिक में करीब 13,000 रसायनों की पहचान की थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इनमें से केवल छह फीसदी रसायन ऐसे हैं, जिन्हें वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनियमित किया जाता है। इसके अलावा कई खतरनाक रसायनों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल के सहयोग से तैयार की गई स्टेट ऑफ द साइंस ऑन प्लास्टिक केमिकल्स नामक रिपोर्ट के मुताबिक, जितने भी तरह के प्लास्टिक का अध्ययन किया गया है वे सभी हानिकारक रसायन छोड़ते हैं। कभी बेहद उपयोगी समझा जाने वाला प्लास्टिक आज दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। बुनियादी जानकारी का आभाव... रिपोर्ट के मुताबिक, प्लास्टिक में पाए जाने वाले एक चौथाई से अधिक

ज्ञात रसायनों की पहचान के बारे में बुनियादी जानकारी का अभाव है। आधे से अधिक के बारे में उनके कार्यों और प्रयोगों के बारे में पब्लिक डोमेन में अस्पष्ट जानकारी है। कौन सा देश कितने प्लास्टिक का उत्पादन कर रहा है और कितना प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है, इस बारे में भी आंकड़ों का आभाव है। यह बेहद चिंताजनक है कि 10 हजार से अधिक रसायनों से जुड़े खतरों को लेकर जानकारी का आभाव है। प्लास्टिक में उपयोग के लिए 1,300 से अधिक रसायनों का व्यापार किया जाता है और अच्छी तरह से अध्ययन किए गए प्लास्टिक प्रकारों में पाए जाने वाले 29 से 66 फीसदी रसायन चिंता का विषय हैं। यानी पैकेजिंग से लेकर सामान्य इस्तेमाल तक के प्लास्टिक के सभी प्रमुख प्रकारों में 400 से अधिक खतरनाक रसायन मौजूद हैं। वैश्विक स्तर पर हर साल करीब 40 करोड़ टन प्लास्टिक उत्पादित किया जाता है। इसमें से केवल नौ फीसदी प्लास्टिक ही रीसाइकल किया जाता है। यदि इस समस्या पर गंभीरता से गौर न किया गया तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जगह बनाने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा 2040 तक करीब 2.9 करोड़ टन पर पहुंच जाएगी।

CAA के खिलाफ दुष्प्रचार देश हित में नहीं... कौमी एकता से ही राष्ट्र मजबूत होगा

भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के समय अपने घोषणापत्र में किये गये एक और वायदे को पूरा कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े देश में आचार संहिता लागू होने से कुछ दिनों पहले सीएए के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। बीजेपी इसे मोदी की गारंटी बता रही है। 2019 में बीजेपी ने कुछ जो बड़े वादे किये थे उसमें जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म किया जाना, अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण में आ रही बाधा को दूर करना, तीन तलाक को खत्म करने का कानून बनाना और अब सीएए को भी अमली जामा पहना दिया गया है। सबसे बड़े वादे की बात की जाये तो समान नागरिक संहिता (एनआरसी) को मोदी सरकार पांच वर्षों तक पूरा नहीं कर पाई। अपवाद के रूप में उत्तराखंड में जरूर यूसीसी लागू हो गया है। मोदी सरकार ने जिस तरह से वायदों को पूरा किया है उसके चलते वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के आम चुनाव में काफी कुछ बदला गया है, लेकिन दस सालों में मोदी सरकार मुसलमानों को विश्वास नहीं हासिल कर सकी। भाजपा से मुस्लिम मतदाताओं की दूरी का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है।

बीजेपी को तमाम चुनावों में करीब 8 प्रतिशत मुसलमानों ने ही वोट दिया, लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नजर आ रही है। सरकारी नुमांइदे कहते हैं कि देश में जिस तरह से तुष्टिकरण की सियासत को बढ़ावा दिया गया था, ऐसे में बीजेपी के लिये मुसलमानों का दिल जीतना आसान नहीं है। इसीलिये सीएए जैसे कानून की भी मुसलमानों के बीच मुखालफत होने लगती है, जबकि इसका भारत के किसी भी नागरिक से कोई लेना-देना ही नहीं है। सीएए किसी की नागरिकता लेने के लिये नहीं बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने वाला कानून है, जो अपने देशों में अल्पसंख्यक होने के कारण वर्षों से पीड़ित हो रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जब नागरिकता संशोधन बिल लाया गया तो इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुए थे। तब आंदोलन में शामिल मुस्लिमों का मानना था कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों को तो नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन मुसलमानों को यह सुविधा नहीं दी गई है। उनके मन में यह बात घर कर गई कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह रही कि 2019 के बाद हुए राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी मुसलमानों का पहले वाला वोटिंग पैटर्न कायम रहा। वर्ष 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव में 77 प्रतिशत मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले थे। 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में 75 प्रतिशत मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले। वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 79 प्रतिशत मुसलमानों ने सपा को वोट किया। इसकी वजह थी कि ये पार्टियां भाजपा के खिलाफ मुसलमानों को बरगलाने में सफल रही थीं।

हालांकि, अब माहौल काफी बदल गया है। अपवाद को छोड़कर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु अपनी कौम को यह बता रहे हैं कि वह इस कानून को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं पालें, क्योंकि इससे किसी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं होगा। किसी की नागरिकता नहीं जायेगी, लेकिन ओवैसी जैसे नेता जरूर सीएए के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। सीएए को लेकर अधिसूचना जारी होते ही विपक्षी पार्टियों ने भी मुस्लिमों के मन में उठ रही शंकाओं को मुद्दे का रूप देना शुरू कर दिया है ताकि लोकसभा चुनाव में नफा-नुकसान के लिहाज से अपनी रणनीति तैयार कर सकें। इससे कई लोकसभा सीटों पर गैर बीजेपी पार्टियों को फायदा मिल सकता है।

बात उत्तर प्रदेश की कि जाये तो यहां करीब 29 लोकसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। यही वजह है कि भाजपा ने पसमांदा मुस्लिम समाज को साधने के लिए दो साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। योगी सरकार-टू में पसमांदा समाज के दानिश आजाद अंसारी को राज्यमंत्री बनाया गया।

खजराना गणेश मंदिर की दानपेटी से निकले 1.75 करोड़ रुपए...

खजराना गणेश मंदिर में लगी दान पेटियों से 1.75 करोड़ रुपए की राशि निकली है। अभी मंदिर की दान पेटी से निकले सिक्कों की गिनती का काम चल रहा है। पांच दान पेटियां अभी खुलना बाकी है। नोटों की गणना चल रही है। सम्भवतः एक दो दिनों में नोटों की गिनती का काम पूरा हो जाएंगा। दान की राशि लगभग दो करोड़ रु तक पहुंच जाएंगी।

लाखों नागरिकों की श्रृध्दा के केंद्र खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों से निकली दान राशि की गणना अभी भी जारी है। दान पेटियों से निकले नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। दान पेटियों से अब तक एक करोड़ 65 लाख रुपए की राशि निकल चुकी है। जबकि दान पेटियों से निकले लगभग 7 लाख के सिक्कों की गिनती अभी जारी है। इस तरह इस बार 5 माह के अंतराल में खोली गई दान पेटियों से लगभग 1 करोड़ 72 लाख की राशि निकलने का अनुमान है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के द्वारा मंदिर के परिसर में मौजूद प्रशासनिक कार्यालय के सभागार में दान के पैसे गिनने का काम किया जा रहा है। इस पूरे काम की सीसीटीवी के माध्यम से रिकॉर्डिंग की भी की जा रही है।

दान में दे दी अपनी परेशानियां

भक्तों के द्वारा मंदिर में लगी दान पेटी में पैसे तो चढ़ाए ही गए हैं उसके साथ ही अपनी परेशानियों को भी दान कर दिया है। इस बार दान पेटियों से बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा भगवान गणेश जी कोअपनी परेशानी के संबंध में लिखे गए पत्र भी निकले हैं। जिन्हें गणेश जी को अर्पित कर दिया गया है। इन पत्रों में किसी ने अपने प्यार को दिलाने का आग्रह किया है तो किसी ने नौकरी मांगी है। किसी ने कर्ज से मुक्ति मांगी है तो किसी ने रईस जिंदगी मांगी है। बंद हो गए नोट भगवान को अर्पित मंदिर में जाकर दान पेटी में पैसा चढ़ाने वाले लोगों की मानसिकता भी उजागर होकर सामने आई है। भारत सरकार की पहल पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा 2000 रु. के जो नोट बंद किए गए थे। वह नोट अभी भी लोगों के पास है और लोगों के द्वारा अब उन नोट का उपयोग मंदिर में भगवान को चढ़ाने में किया जा रहा है। मंदिर की दान पेटी की गणना में दान पेटियों से बंद हो चुके 2000 के 6-7 नोट भी निकले हैं। इसी तरह विदेशी करेंसी भी निकली है। साथ ही सोने चांदी के कुछ जेवरात भी दान पेटियों से निकले हैं।

विदेश जाने के लिए मांगी इलेक्शन ड्यूटी से मुक्ति

निर्वाचन कार्यालय में आने लगे आवेदन, नहीं करना है ड्यूटी

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसर ने विदेश जाने के नाम पर लोकसभा चुनाव की ड्यूटी करने से मुक्ति मांगी है। इसके साथ ही निर्वाचन कार्यालय में इलेक्शन ड्यूटी नहीं करने के लिए आवेदन आना शुरू हो गए हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही इलेक्शन की ड्यूटी लगाना और ड्यूटी करने वालों के प्रशिक्षण के कार्य को अंजाम देने की कवायद शुरू हो गई है। वैसे तो प्रशिक्षण के कार्य का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारी की जा रही है। इसी बीच जिन लोगों की इलेक्शन में ड्यूटी लगी है उन लोगों के द्वारा इस ड्यूटी से मुक्ति पाने के लिए कसरत शुरू कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों जिला कलेक्ट्रेट में स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में इलेक्शन की ड्यूटी मुक्ति के आवेदन आना शुरू हो गए हैं। इंदौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए 18 अप्रैल से नामा-कन पत्र भरने का कार्य शुरू होगा। निर्वाचन कार्यालय में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसर के इलेक्शन की ड्यूटी से मुक्ति के आवेदन आए हैं। **अलग अलग कारणों से जाना है विदेश** : इस आवेदन में एक महिला प्रोफेसर ने जापान का वीजा भी लगा रखा है। कहना है कि बिटिया की पढ़ाई पूरी हो गई है, उसको डिग्री मिलना है। इस मौके पर उन्हें जाना है। एक अन्य महिला प्रोफेसर ने अमरीका जाने की जानकारी दी है। उनकी बिटियां की डिलेवरी होने वाली है और संभालने वाला वहां कोई नहीं है। तीसरे पुरुष प्रोफेसर है जो अमरीका जा रहे है। तीनों ने वीजा के लिए आवेदन कर रखा है।

भारत पर बुरी नजर डाली तो सशस्त्र बल मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार...

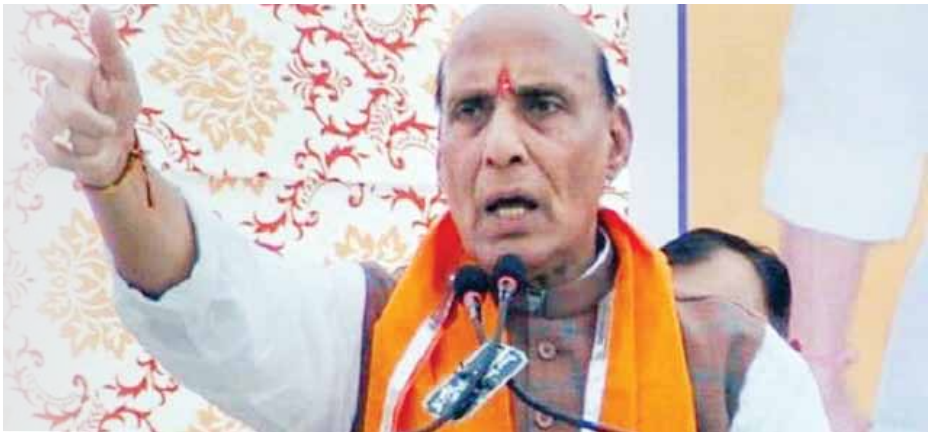

रक्षा मंत्री ने कहा कि जब प्रौद्योगिकी की बात आती है, तो विकासशील देशों के पास दो विकल्प-नवाचार और अनुकरण- होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को अनुकरण करने वाला बनाने के बजाय प्रौद्योगिकी निर्माता बनाने पर विशेष जोर दे रही है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर भारत को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बृहस्पतिवार को जोर दिया और कहा कि सशस्त्र बल अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और अगर कोई बुरी नजर डालता है तो मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ करीब चार साल से सीमा विवाद और चीनी सेना के हिंद महासागर में प्रवेश को लेकर चिंताओं की पृष्ठभूमि में एक सवाल पर उनका यह बयान आया है। एनडीटीवी द्वारा आयोजित 'डिफेंस समिट' में उन्होंने कहा, हर समय युद्ध के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। हर समय। चाहे बिल्कुल शांति काल हो लेकिन हमारी तैयारी बराबर होनी चाहिए। सिंह से सीमा पर भारत के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के साथ-साथ सरकार द्वारा सीमा पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में पूछा गया था। रक्षा मंत्री ने कहा, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि भारत ने कभी भी दुनिया के किसी भी देश पर हमला नहीं किया, किसी भी देश की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। लेकिन, अगर कोई भारत पर बुरी नजर डालता है, तो देश अब मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। सिंह ने कहा कि देश की रक्षा प्रणाली लोगों के दृष्टिकोण के अनुरूप सरकार द्वारा एक नयी ऊर्जा से प्रेरित है और इसके परिणामस्वरूप भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर सेना के साथ वैश्विक मंच पर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का रक्षा तंत्र आज पहले से कहीं अधिक मजबूत है क्योंकि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे भारतीयता की भावना के साथ मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने नजरिया को वर्तमान और पिछली सरकार के बीच प्रमुख अंतर बताया और कहा कि मौजूदा सरकार भारत के लोगों की क्षमताओं में दृढ़ता से विश्वास करती है, जबकि पहले सत्ता में रहने वाले लोग उनकी क्षमता के बारे में कुछ हद तक सशंकित थे। सिंह ने कहा, केंद्र में शक्तिशाली नेतृत्व के कारण आज हमारी सेनाओं में दृढ़ इच्छाशक्ति है। हम सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में कुछ स्थानों पर साढ़े तीन साल से अधिक समय से टकराव की स्थिति में हैं, जबकि दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने को सरकार द्वारा लाया गया सबसे बड़ा बदलाव बताया और कहा कि यह भारत के रक्षा क्षेत्र को एक नया आकार दे रहा है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों को भी रेखांकित किया, जिनमें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना, घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 75 प्रतिशत आरक्षित करना और आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण करना शामिल है। उन्होंने कहा, वार्षिक रक्षा उत्पादन, जो 2014 में लगभग 40,000 करोड़ रुपये था, अब रिकॉर्ड 1.10 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। उन्होंने कहा, नौ-दस साल पहले रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ रुपये था जो आज बढ़कर 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हमने 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपये का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब प्रौद्योगिकी की बात आती है, तो विकासशील देशों के पास दो विकल्प-नवाचार और अनुकरण- होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को अनुकरण करने वाला बनाने के बजाय प्रौद्योगिकी निर्माता बनाने पर विशेष जोर दे रही है।

फोरलेन के लिए अभी और इंतजार, 2 केंद्रीय योजनाएं अब भी अधूरी

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अन्य शहरों से जोड़ने वाले दो प्रमुख मार्गों को फोर लेन बनाने की योजना पूरी नहीं हो सकी है। इंदौर-खंडवा-एदलाबाद और इंदौर-हरदा-बैतूल मार्ग को टू लेन से फोर लेन किया जाना है। केंद्रीय योजना के तहत बनाए जाने वाले दोनों मार्गों पर निर्माण पूरा होने में करीब दो साल का समय लगेगा। इंदौर-हरदा-बैतूल मार्ग को फोर लेन करने की कवायद करीब आठ साल से चल रही है। कई बार इसकी घोषणा हुई, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पाया। करीब 272 किमी लंबे इंदौर-हरदा-बैतूल हाईवे के हरदा से इंदौर की तरफ वाले काम को गत वर्ष से गति मिली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अलग-अलग चरणों में इसका निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण में बैतूल से हरदा तक का काम लगभग पूरा हो चुका है। हरदा से कन्नौद तक सड़क निर्माण का काम जारी है। फोर लेन प्रोजेक्ट के तहत इंदौर से करनावद (राघोगढ़) ग्रीनफील्ड हाईवे का काम भी शुरू हो गया है। बायपास स्थित एमआर-10 चौराहे से राघोगढ़ तक 26।65 किमी सड़क निर्माण की लागत 358 करोड़ रुपये है। इंदौर के मुहाने से काम शुरू हो चुका है। अभी दो साल का समय इंदौर से हरदा तक फोर लेने का काम पूरा होने में लगेगा।

अलाइनमेंट में बदलाव के कारण देरी से शुरू हुआ काम

एनएचएआइ द्वारा 216 किमी लंबे इंदौर-खंडवा-एदलाबाद मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। कई बार इसे फोर लेन करने की घोषणा हुई, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। गत वर्ष भूमिपूजन के बाद का शुरू किया गया। सड़क के अलाइनमेंट में कई बार बदलाव के कारण काम देरी से शुरू हुआ। यह सड़क पांच चरणों में बनाई जा रही है। पहले चरण में तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक 33 किमी सड़क का निर्माण होगा। इसके बाद बलवाड़ा से धनगांव तक 40 किमी हिस्से में सड़क बनेगी। कुल लागत 950 करोड़ रुपये है।

▶ इंदौर-बैतूल हाईवे का काम जारी है। इसमें इंदौर से करनावद (राघोगढ़) तक 26।65 किमी लंबी सड़क बनाई जा रही है, वहीं इंदौर-एदलाबाद रोड का काम भी तेज गति से जा रही है। तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक सुरंग और सड़क का काम भी तीव्र गति से किया जा रहा है। अगले साल तक काम पूरा कर लिया जाएगा।
- सुमेश बांझल, महाप्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अब हेल्थ ड्रिंक के नाम पर नहीं बेच पाएंगे ड्रिंक्स...

बोर्नविटा ने वास्तव में 'मालिकाना भोजन' के तहत लाइसेंस प्राप्त किया है, जिसमें खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) भोजन के लेबल पर निकटतम खाद्य उत्पाद श्रेणी का नाम घोषित करना होगा। एफबीओ ने बोर्नविटा को अनाज आधारित पेय मिश्रण घोषित किया है। इन दिनों कई स्टोर्स में हेल्दी ड्रिंक के नाम पर कई तरह के पेय पदार्थ उपलब्ध है। हेल्दी ड्रिंक का टैग लेकर बाजार में कई अनहेल्दी ड्रिंक भी उपलब्ध हैं जो कि बच्चों से लेकर युवाओं के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर सकती है। वहीं भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 भी है जिसमें स्वास्थ्य पेय का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

इसी बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपभोक्ता मामलों के विभाग को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि कोई भी पेय पदार्थ (जिसमें बॉर्नविटा और इस तरह के उत्पाद शामिल है) उन्हें दुकानों में स्वास्थ्य पेय की श्रेणी के तहत नहीं बेचा जाना चाहिए। इस मामले पर एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को पत्र लिखा है। उन्होंने सिफारिश की है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी साइटों से ड्रिंक और बेवरेज को हेल्दी ड्रिंक की श्रेणी से हटाने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। आयोग ने इस पत्र की एक प्रति स्वास्थ्य और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को भी कार्रवाई के लिए भेजी है। पत्र भेजने के बाद आयोग ने 23 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। एनसीपीसीआर ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिवों को भी पत्र लिखा है जिसमें उसने कुछ स्वास्थ्य-पाउडर पेय पदार्थों

के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है। इसमें एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेचे जा रहे प्रोडक्ट ने दावा किया कि इसमें अधिक मात्रा में चीनी और कई हानिकारक सामग्री शामिल है। खासतौर से बच्चों के लिए बोर्नविटा जैसे हेल्थ ड्रिंक भी काफी हानिकारक है।

एनसीपीसीआर ने बोर्नविटा बनाने वाली मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को नोटिस जारी किया था। एफएसएसएआई ने एनसीपीसीआर को दिए अपने जवाब में कहा कि 'हेल्थ ड्रिंक' शब्द को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। बोर्नविटा ने वास्तव में 'मालिकाना भोजन' के तहत लाइसेंस प्राप्त किया है, जिसमें खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) भोजन के लेबल पर निकटतम खाद्य उत्पाद श्रेणी का नाम घोषित करना होगा। एफबीओ ने बोर्नविटा को अनाज आधारित पेय मिश्रण घोषित किया है। मोंडेलेज़ इंडिया के प्रतिनिधियों ने भी आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के दौरान कहा कि बॉर्नविटा एक स्वास्थ्य पेय नहीं है।

साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर, पटरी से उतरी कई बोगियां

अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर रात 1.04 बजे ये हादसा हुआ है। हादसा टालने के लिए लोको पायलट ने ब्रेक भी लगाए मगर टक्कर रोकना मुमकिन नहीं रहा।अधिकारियों का कहना है कि टक्कर के बाद इंजन, जनरल कोच समेत चार बोगियां पटरी से उतर गई। राजस्थान के अजमेर में सोमवार 18 मार्च को एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। ये ट्रेन हादसा एक मालगाड़ी और साबरमती एक्सप्रेस के बीच टक्कर होने की वजह से हुआ है। हादसा सोमवार तड़के हुआ है जब साबरमती एक्सप्रेस की चार बोगियां पटरी से नीचे उतर गई।

अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर रात 1.04 बजे ये हादसा हुआ है। हादसा टालने के लिए लोको पायलट ने ब्रेक भी लगाए मगर टक्कर रोकना मुमकिन नहीं रहा।अधिकारियों का कहना है कि टक्कर के बाद इंजन, जनरल कोच समेत चार बोगियां पटरी से उतर गई।

हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। राहत बचाव कार्य में जुटी टीमों ने घायलों को अजमेर में अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज जारी है। चश्मदीदों का कहना है कि रात को यात्री सो रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। जोरदार टक्कर के कारण हुई आवाज से सभी लोग अचानक उठे। इसके साथ ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी।

घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के साथ अतिरिक्त मंडल रेलवे प्रबंधक (एडीआरएम) और वरिष्ठ अधिकारी सहित बचाव दल मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू टीम अब इंजन और डिब्बों को पटरी पर लाने में जुटी हुई है। वहीं रेलवे की पटरियों की मरम्मत का काम भी जारी है। ट्रैक बहाली का काम शुरू हो चुका है। बता दें कि इस एक्सीडेंट के कारण छह ट्रेनें भी प्रभावित हुई है। अधिकारी इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए कार्य योजना भी बना रहे है।

सबसे पुरानी पार्टी में मोदीजी जैसे मजबूत नेता की कमी..

खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने सभी मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक पद्मजा जिला कांग्रेस समितियों के पुनर्गठन के दौरान त्रिशूर में उनके प्रत्याशियों को तरजीह न मिलने से भी खफा थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कई नेता त्रिशूर में करुणाकरण का स्मारक बनाने के इच्छुक नहीं थे।

पद्मजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मुझे किसी भी समिति में शामिल नहीं किया गया था। पार्टी के भीतर चार-पांच लोग मुझे त्रिशूर से बाहर निकालने और हर जगह मेरे लिए समस्याएं पैदा करने के लिए काम कर रहे थे। जब मैनें इस बारे में शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की तो पार्टी नेतृत्व ने कोई सुनवाई नहीं की। देश में लोकसभा चुनाव होने से पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। राजनैतिक दल वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए जी-जान से जुटे हुए हैं। वहीं, विभिन्न राजनेता भी दल परिवर्तन कर अपना राजनैतिक भविष्य सुरक्षित करने में लगे हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थीं। अब आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी जैसे मजबूत नेता की कमी है।

हर पार्टी को पीएम मोदी जैसे नेता की जरूरत

भाजपा में शामिल होने के बाद केरल लौटी पद्मजा का शुक्रवार को हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। वहां एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए पद्मजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने का उन्हें दुख है, लेकिन वह वहां अपमानित हो रही थीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में समस्याओं का सामना करने के बाद भी वे लंबे समय तक कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। फिर पीएम मोदी की कार्यशैली देखकर उन्हें लगा कि हर पार्टी को पीएम मोदी जैसे मजबूत नेता की जरूरत है। कांग्रेस के पास ऐसे नेता की कमी है। यह सब देख कर ही उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया।

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शीर्ष नेताओं के पास

पदाधिकारियों से मिलने का भी समय नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जब वह दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय गईं तो उन्होंने पाया कि सोनिया गांधी किसी से नहीं मिलती हैं। इतना ही नहीं राहुल गांधी के पास भी समय नहीं है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वहां रहने का अब कोई मतलब नहीं है। पद्मजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मुझे किसी भी समिति में शामिल नहीं किया गया था। पार्टी के भीतर चार-पांच लोग मुझे त्रिशूर से बाहर निकालने और हर जगह मेरे लिए समस्याएं पैदा करने के लिए काम कर रहे थे। जब मैनें इस बारे में शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की तो पार्टी नेतृत्व ने कोई सुनवाई नहीं की।

भाई को दिया ये जवाब : प्रेस कांफ्रेंस में पद्मजा में प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल ममकुत्तथिल की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल ने उनके माता-पिता के बारे में जो बातें कही हैं, वे उनकी मां का अपमान करने जैसी हैं। वे इन टिप्पणियों को लेकर राहुल ममकुत्तथिल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराएंगी। इस दौरान पद्मजा ने अपने भाई को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके भाई और कांग्रेस सांसद के मुरलीधरन ने भी कई बार पार्टी बदली है, तब मैंने कभी उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। अब वे मुझे लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन, हमें अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को अलग रखने की जरूरत है। मेरा राजनीतिक जीवन अलग है।

तीन दिन पहले तक कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल रहीं, पद्मजा ने गुरुवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस फैसले से आहत पद्मजा के भाई ने कहा है कि उनके पिता की आत्मा इस कृत्य के लिए उन्हें माफ नहीं करेगी। वडकारा लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद मुरलीधरन ने कहा कि वे पद्मजा से सभी संबंध तोड़ रहे हैं। चार बार मुख्यमंत्री रहे करुणाकरण की बेटी पद्मजा का भाजपा सदस्य बनना इस दृष्टिकोण से भी अहम है, क्योंकि भाजपा अपना जनाधार मजबूत करने के लिए दक्षिण भारत समेत ऐसे इलाकों पर फोकस कर रही है, जहां अभी पार्टी के पास पर्याप्त वोट और सांसद-विधायक नहीं हैं। केरल भी उन राज्यों में शामिल है, जहां भाजपा को अभी सत्ता पर असर डालने के नजरिए से शून्य से शुरुआत करनी है।

कांग्रेस से नाराजगी का कारण : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पद्मजा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से नाराज चल रही थीं। सूत्रों के मुताबिक सियासी मात के बाद पद्मजा राज्यसभा नामांकन पाने की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन पार्टी ने विचार नहीं किया। उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में भी टिकट मिलने की संभावना न के बराबर थी। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने सभी मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक पद्मजा जिला कांग्रेस समितियों के पुनर्गठन के दौरान त्रिशूर में उनके प्रत्याशियों को तरजीह न मिलने से भी खफा थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कई नेता त्रिशूर में करुणाकरण का स्मारक बनाने के इच्छुक नहीं थे।

न्यायालय केवल भवन नहीं न्याय का मंदिर-राज्यपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर के लिये ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर एक ही दिन में तीन बड़ी सौगातें मिली हैं। नए एयर टर्मिनल, जिला एवं सत्र न्यायालय का आधुनिक भवन और एमआईटीएस कॉलेज के नए भवन के साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त हुआ है।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि न्यायालय केवल भवन नहीं होता बल्कि न्याय का मंदिर होता है। मंदिर में आने वाले गरीब, शोषित और जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर न्याय मिले, यह जरूरी है। राज्यपाल श्री पटेल ने ग्वालियर में नवनिर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन व इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जे. के. माहेश्वरी व न्यायमूर्ति श्री एस. सी. शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलिमथ एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री रोहित आर्या कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। ग्वालियर को बेहतर वातावरण एवं सुविधाओं के साथ न्यायिक सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 115 करोड़ 41 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के लोकार्पण अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि हमारे देश की न्यायपालिका श्रेष्ठ है और इसे विश्व भर के देश भी मानते हैं। हमारे देश की न्यायपालिका ने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी कई नवाचार किए हैं।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सभी को बेहतर न्याय मिले, इसके लिए कई नवाचार किए गए हैं। बंदीगृहों में बंदियों को बेहतर सुविधायें मिलें, इसके लिये भी कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल में बंद 12 से 14 साल के बच्चे जिनसे छोटे-छोटे अपराध हो गए हैं और जेल में बंद हैं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये बंदीगृहों में शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाना चाहिए। ग्वालियर में निर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय का नया भवन जरूरतमंदों को न्याय उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका यह तीनों लोकतंत्र के मजबूत स्तम्भ हैं। ग्वालियर में जिला एवं सत्र न्यायालय का आधुनिक भवन बनकर तैयार हुआ है। इस न्यायालय के माध्यम से लोगों को न्याय मिलेगा, साथ ही आधुनिक भवन में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगीं। वकीलों एवं न्यायधीशों को भी अच्छे वातावरण में कार्य करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नए भवन के उद्घाटन अवसर पर बारकाउंसिल के माध्यम से वकीलों की सुविधाओं के लिये जो भी मांग रखी गई है उसे राज्य सरकार पूरा करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर के लिये आज ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर एक ही दिन में तीन बड़ी सौगातें मिली हैं। नए एयर टर्मिनल, जिला एवं सत्र न्यायालय का आधुनिक भवन और एमआईटीएस कॉलेज के नए भवन के साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी आज प्राप्त हुआ है। हम सबके लिये यह गौरव की बात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि न्यायालय में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पक्षकार होता है। उसे समय पर न्याय मिले इसकी चिंता हम सबको करना चाहिए। मध्यप्रदेश में न्यायालयीन भवनों के निर्माण के साथ न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है।

इंदौर-उज्जैन को सिक्स लेन में खर्च होंगे 950 करोड़

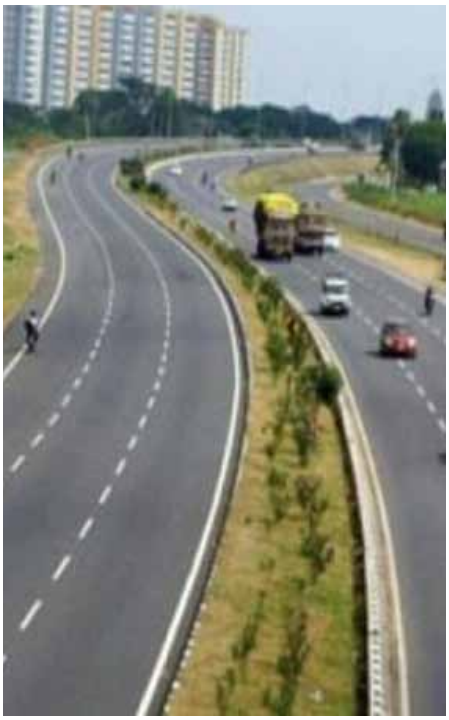

सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इन दिनों उज्जैन को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों को बेहतर बनाने में जोर दिया जा रहा है। इंदौर-उज्जैन फोरलेन रोड़ को सिक्स लेन में तबदील किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर शासन ने सड़क निर्माण के लिए बजट भी निर्धारित कर दिया है। करीब 950 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अब एमपीआरडीसी को सड़क निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है। अगले कुछ महीनों में सड़क की डिजाइन से लेकर डीपीआर और टेंडर निकाले जाएंगे।

सिंहस्थ में देशभर से पचास लाख से अधिक श्रद्धालुओं रोजाना पहुंचेंगे, जो विभिन्न मार्ग से होते हुए उज्जैन आएंगे। इनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार ने उज्जैन से जुड़ने वाली प्रमुख सड़कों को सुधारने पर जोर दिया है। इंदौर-उज्जैन रोड़ को प्राथमिकता देते हुए ढ़ाई साल में काम पूरा करने का लक्ष्य दिया है। सिक्स लेन सड़क के लिए एमपीआरडीसी अगले कुछ सप्ताह में अपना प्रेजेंटेशन दे सकती है, जिसमें सड़क की डिजाइन और निर्माण लागत के बारे में बताया जाएगा। 48 किमी लम्बी इस सड़क पर काम शुरू करने से पहले एजेंसी को वैकल्पिक मार्ग बनना होगा। ताकि लोगों को उज्जैन आने-जाने में परेशानी नहीं होगी। यहां तक कि एक दिशा का काम पूरा होने के बाद ही सड़क के दूसरे हिस्सा बनाना होगा। सड़क को सिक्स लेन में तबदील करने के लिए एमपीआरडीसी के पास यू तो साढ़े तीन साल का समय है, लेकिन छह महीने डीपीआर, टेंडर और डिजाइन बनाने में निकल जाएगा। एमपीआरडीसी के राकेश जैन का कहना है कि प्रोजेक्ट संबंधित जानकारी आने के बाद टेंडर निकाला जाएगा। उसमें भी चार से पांच महीने का समय लगेगा। वर्क आर्डर के बाद निर्माण शुरू होगा। इस पूरी प्रक्रिया में दिसंबर तक का समय लगेगा।

इंदौर में निभाई 296 साल से चली आ रही परंपरा..

सबसे पहले जली राजवाड़ा पर सरकारी होली...

फाल्गुन पूर्णिमा पर भद्रा के साये के बीच रविवार को इंदौर में जगह-जगह होलिका दहन हुआ। सबसे पहले 296 साल से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए शाम सात बजे सरकारी होली का दहन राजवाड़ा पर किया गया। यहां होली दहन के पूर्व होलिका का पूजन होलकर राजवंश के रिचर्ड होलकर ने किया। स्वच्छता में नंबर वन शहर पर्यावरण संरक्षण की भावना से होलिका दहन में गाय के गोबर के कंडों का उपयोग हुआ। वरिष्ठों ने गेहूं की बालियां सेंकी और परिक्रमा लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की। सोमवार को धुलेंडी पर रंगभरी होली खेली जाएगी।

दहन के बाद उड़ाया गुलाल

शहर में रातभर होलिका दहन का सिलसिला चलता रहा। गली, मोहल्लों, चौराहों और कालोनियों के साथ ही टाउनशिप में कार्यक्रम हुए। दहन के बाद रंग-गुलाल उड़ाया गया। स्वच्छता में नंबर इंदौर में पर्यावरण संरक्षण और गोशालाओं को स्वावलंबी बनाने की भावना से लकड़ी के बजाय कंडों का उपयोग किया गया। गोसेवा विभाग संयोजक मनोज तिवारी ने बताया कि पंचदेव मंदिर एलआइजी, मालवा मिल व्यापारी एसोसिएशन, हैंडलूम व्यापारी एसोशिएशन सहित अधिकतम स्थानों पर कंडों से होलिका दहन गोशाला को स्वावलंबी बनाने की भावना से किया गया।

सिंहस्थ को लेकर इंदौर में होने वाले कामों के लिए सेल का गठन..

वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां उज्जैन में शुरु हो चुकी है। वहीं इंदौर से होने वाले कामों को लेकर भी इंदौर में नगर निगम और जिला प्रशासन ने भी अपनी अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। सिंहस्थ को इंदौर में सेल का गठन किया गया है। इस सेल में शामिल नगर निगम के अफसरों को हर 15 दिन में कार्यों की समीक्षा करने के साथ निगमायुक्त को प्रगति रिपोर्ट देना होगी। सिंहस्थ महापर्व-2028 को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर शहर में कराए जाने वाले कार्यों के लिए सेल का गठन निगमायुक्त शिवम वर्मा ने किया है। सिंहस्थ सेल में ड्रेनेज विभाग के अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन, जनकार्य विभाग के अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, जनकार्य विभाग के अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी, ड्रेनेज विभाग के कार्यपालन यंत्री सुनील गुप्ता, जनकार्य विभाग के सहायक यंत्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी, योजना शाखा के सहायक यंत्री नरेश जायसवाल, उपयंत्री पराग अग्रवाल, ड्रेनेज विभाग के सहायक यंत्री आएएस देवड़ा और उपयंत्री आकाश जैन है। निगम के इन अफसरों को सिंहस्थ से संबंधित कामों के प्रस्तावों को समयावधि में तैयार कराते हुए कार्यों का क्रियान्वयन कराने सहित मॉनिटरिंग करना होगी। इसके साथ ही हर 15 दिन की अवधि में समीक्षा बैठक रखते हुए निगमायुक्त वर्मा को कार्य कि प्रगति संबंधी रिपोर्ट देना होगी। सिंहस्थ को लेकर बनी सेल सड़क से लेकर ड्रेनेज से संबंधित कार्य करेगी, क्योंकि इंदौर शहर की ड्रेनेज का पानी कबीटखेड़ी स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पर जाने के बाद ट्रीट होता है। ट्रीट वाटर उज्जैन की शिप्रा नदी में छोड़ा जाता है। सिंहस्थ के दौरान शिप्रा में गंदा पानी न जाए। इस पर पूरा ध्यान सेल को रखना होगा।

रीजनल पार्क और मेघदूत गार्डन को ठेके पर देने की तैयारी, री-डेवलपमेंट होगा

शहर के सबसे बड़े मनोरंजन स्थल रीजनल पार्क को ठेके पर देने की कवायद नगर निगम में पिछले कई वर्षों से चल रही है। पार्क को ठेके पर देने के लिए निगम ने पिछले दिनों टेंडर जारी किए थे, लेकिन रेट कम मिलने के कारण निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही कंसल्टेंट कंपनी को भी रीजनल पार्क से बाहर कर दिया है। अब नए सिरे से पार्क और कंसल्टेंट के टेंडर होगे। रीजनल पार्क के साथ साथ शहर का एक और मनोरंजन स्थल मेघदूत गार्डन को भी ठेके पर देने की तैयारी निगम कर रहा है। राजीव गांधी प्रतिमा चौराहा से चंद कदमों की दूरी पर पीपल्यापाला तालाब किनारे खाली पड़ी जमीन पर रीजनल पार्क बनाया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने यह पार्क बनाया और फिर निगम के हवाले कर दिया ताकि निगम पार्क का संचालन और संधारण कर सके। अब इस पार्क का रखरखाव और संचालन करने में निगम के हाथ-पैर फूलने लगे हैं। देखरेख के अभाव में पार्क धीरे-धीरे चर्बाद होने लगा है।

पार्क को 27 वर्ष के लिए ठेके पर देने का फैसला

बताया गया है की पार्क को 27 वर्ष के लिए ठेके पर देने का फैसला लिया गया और पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर पार्क का ठेका देने को लेकर टेंडर पिछले दिनों बुलाए गए। साथ ही टेंडर डालने से पहले ठेकेदार एजेंसियों की प्री-बीट मीटिंग बुलाई गई ताकि टेंडर आ जाए। इसके बाद रीजनल पार्क को ठेके पर लेने के लिए टेंडर आए, लेकिन निगम ने टेंडर निरस्त कर दिए। कारण पार्क को ठेके पर लेने के सालाना रेट कम आना बताया जा रहा हे जो कि । करोड़ ।। लाख रुपए सालाना है। पार्क का टेंडर निरस्त करने के साथ कंसल्टेंट मेहता एसोसिएट्स को भी बाहर कर दिया गया है।

ठेके पर देने के लिए दो से तीन बार टेंडर हुए : अब रीजनल पार्क के साथ मेघदूत गार्डन को भी ठेके पर देने और कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए पीपीपी मॉडल पर टेंडर बुलाए जाएंगे। इसकी तैयारी उद्यान विभाग ने शुरू कर दी है। मालूम हो कि रीजनल पार्क को ठेके पर देने की कवायद तत्कालीन निगमायुक्त आशीष सिंह के समय से चल रही है। इसके चलते पार्क को ठेके पर देने के लिए दो से तीन बार टेंडर हुए, लेकिन टेंडर लेने के लिए कोई आगे नहीं आया।

रेट कम होने से टेंडर निरस्त कर दिया गया

पिछले दिनों नगर निगम ने ठेकेदारों की एक बैठक बुलाई ताकि मालूम पड़ सके कि टेंडर क्यों नहीं डाला गया? इसके साथ ही ठेकेदारों से बात कर उनके अनुसार टेंडर शर्तों में बदलाव किया गया। नियम ने उन्हीं शर्तों में बदलाव किया जो मान्य करने लायक थी। रिटेंडर किए गए और पार्क को ठेके पर लेने का टेंडर आ गया, लेकिन रेट कम होने से टेंडर निरस्त कर दिया गया। टेंडर निरस्ती के प्रस्ताव पर मुहर मेयर-इन करेंसिल (एमआइसी) ने भी लगा दी है। हालाकि हर महीने रीजनल पार्क से निगम को 6 लाख 18 हजार रुपए के आसपास इनकम होती है। इस हिसाब से सालभर की इनकम 74 लाख 16 हजार रुपए के करीब होती है। पार्क में मेंटेनेंस के नाम पर इनकम से कम ही पैसा खर्च होता है। बावजूद इसके पार्क की देखरेख ढंग से नहीं होती है।

मेघदूत गार्डन का होगा रि डेवलपमेंट : शहर के पुराने मेधदूत गार्डन का मेंटेनेंस न होने पर बदहाल होता जा रहा है। फाउंटेन (फव्वारे) की सफाई नहीं होती है। वाकिंग ट्रेक पर पेवर ब्लॉक उखड़े पड़े हैं। फाउंटेन बंद पड़े हैं। अनावश्यक घास उगने पर कटाई नहीं होती है। बच्चों के लिए झूलों के नीचे पानी भरने के साथ कीचड़ हो जाता है। जगह-जगह टूट-फूट हो रही पर रिपेयरिंग के काम नहीं हो रहे है। सौन्दर्यीकरण के साथ सिविल वर्क गार्डन में न होने से हालत खराब होती जा रही है।

जल्द होगी कंसल्टेंट की नियुक्ति : बदहाली की तरफ आग्रसर हो रहे मेघदूत गार्डन का रि डेवलपमेंट करने की प्लानिंग निगम कर रहा है। इसके लिए गार्डन को ठेके पर देगा ताकि संचालन-संधारण हो सकें। रि डेवलपमेंट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जा रहा है ताकि ठेकेदार एजेंसी से डीपीआर के अनुसार काम कराने के साथ गार्डन को ठेके पर दिया जा सके। अभी निगम के पास गार्डन होने से यह काम सही ढंग से नहीं हो रहा है. जबकि निगम गार्डन से सालाना 30 लाख रुपए कमा रहा है।

इंदौर जल अभाव क्षेत्र घोषित

बिगड़ते हालात देख प्रशासन ने जिले में नलकूप खनन पर लगाई रोक...

पिछले वर्षों में इंदौर शहर में भूजल के स्तर के भले ही सुधार हुआ है, लेकिन देपालपुर व सांवेर जैसे इलाकों में कृषि कार्य के लिए अत्यधिक भूजल दोहन हो रहा है। दिसंबर 2023 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में इंदौर जिले में 119.3 प्रतिशत भूजल दोहन का आकलन किया गया है। यानि प्राकृतिक रूप से जितना जल पुर्नभरण हो रहा है, उसके मुकाबले हम 19.3 प्रतिशत अधिक भूजल उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण जिला प्रशासन ने अब इंदौर जिले को जल अभाव क्षेत्र घोषित कर नए नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 (अधिनियम) में विहित प्रविधानों के अनुरूप जिले के शहरी एवं ग्रामीण संपूर्ण क्षेत्र को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर 18 मार्च से 30 जून 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है। अवैध रूप से नलकूप खनन करने वालों पर संबंधित राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारी संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में एफआइआर दर्ज करवा सकेंगे। साथ ही मशीनों को जब्त करेंगे। अपर कलेक्टर अपने क्षेत्र के अंतर्गत अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात अनुमति दे सकेंगे। इस तरह के प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये के जुर्माने तथा दो वर्ष तक के कारावास या दोनों से दंडित करने का प्रविधान है।

शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत किए जाने वाले नलकूप खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य योजनांतर्गत नलकूप खनन का कार्य लोकसभा निर्वाचन 2024 की लागू आचार संहिता का पालन करने की शर्त पर कार्य कराया जा सकेगा। जल प्रबंधन विशेषज्ञ सुरेश एमजी के अनुसार हमने एक माह पहले पहले रिंग रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर व होलकर कालेज में रेजिस्टिविटी जियोलाजिक सर्वे किया था। इन दोनों पर जब एक माह बाद पुनः सर्वे किया तो भी पता चला कि भूजल 80 से 100 फीट नीचे पहुंच गया है। जिन इलाकों में भूजल पुर्नभरण पर कार्य हुआ है, वहां भूजल स्तर की स्थिति ठीक है।

▶ इंदौर नगरीय क्षेत्र में भूजल की स्थिति सुधरी है और शहरी क्षेत्र में भूजल निर्भरता कम हुई है। पिछले वर्षों में शहर में नर्मदा पेयजल लाइन का क्षेत्र बढ़ा है, वहीं कई इलाकों में भूजल पुनर्भरण भी हुआ। सांवेर व देपालपुर क्षेत्र में गेहूं की उपज ज्यादा होने के कारण कृषक सिंचाई के लिए भूजल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कृषि को जागरूक कर उन्हें स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। उन्हें इस तरह के संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। इसके अलावा कम जल उपयोग कर ज्यादा फसल उपजाने का अभियान भी इन क्षेत्रों में लागू होना चाहिए।
-सुधीन्द्र मोहन शर्मा, भूजल प्रबंधन विशेषज्ञ

शक्ति केंद्रों को मजबूत करने में जुटी भाजपा

लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा अब अपने शक्ति केंद्रों को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी के निर्देश के बाद वरिष्ठ नेता इन शक्ति केंद्रों पर पहुंचकर पंच परमेश्वर, बूथ त्रिदेव से चौपाल पर चर्चा कर उन्हें विजय संकल्प दिलवा रहे हैं। शक्ति केंद्रों पर नियमित बैठकें हो रही हैं। दरअसल इन शक्ति केंद्रों को मजबूत कर भाजपा इनके माध्यम से महिला वर्ग में पैठ बनाने और उनके शत प्रतिशत मत अपने पक्ष में करने में जुटी है। पार्टी का लक्ष्य शक्ति केंद्रों की अवधारणा को जन-जन तक पहुंचाने की है। इन्हीं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में युवतियों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की योजना भी तैयार की जा रही है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूसिंह रघुवंशी का कहना है कि शक्ति केंद्र की अवधारणा बहुत पुरानी है। जनसंघ के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय शक्ति केंद्र ऐसे स्थानों पर बनाए जाते थे जहां कार्यकर्ताओं से संपर्क साधना आसान हो। इसके लिए सामान्यतः किसी हाट बाजार में शक्ति केंद्र बनाया जाता था। इसका उद्देश्य होता था कि हाट बाजार में आठ-दस गांव के खरीदार, व्यापारी पहुंचते थे। इन सभी से एक ही स्थान पर संपर्क हो सके और पार्टी की विचारधारा इन लोगों तक पहुंचाई जा सके।

शक्ति केंद्र सामान्यतः किसी कार्यकर्ता का कार्यालय, घर या दुकान होता था। समय के साथ इस व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ है। वर्तमान में शक्ति केंद्र चार-पांच बूथ को मिलाकर बनाए जाते हैं। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 2246 बूथ हैं। इस हिसाब से इंदौर लोकसभा क्षेत्र में शक्ति केंद्रों की संख्या 600 के लगभग है। इनमें से करीब 136 शक्ति केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। शक्ति केंद्रों के माध्यम से पार्टी की विचारधारा का प्रचार, प्रसार आसान हो जाता है।

महिलाएं हैं शक्ति केंद्रों की प्रभारी

इंदौर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के कई शक्ति केंद्रों की कमान महिलाओं के हाथ में है। शक्ति केंद्रों पर पंच परमेश्वर, बूथ त्रिदेव जैसी यूनिटें भी हैं। संयोजक, पालक, हितग्राही संयोजक, इंटरनेट मीडिया प्रभारी और आइटी प्रभारी को मिलाकर पंच परमेश्वर यूनिट बनती हैं तो बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलओ को मिलाकर त्रिदेव यूनिट। पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति केंद्रों पर पहुंचकर चौपाल पर पंच परमेश्वर और बूथ त्रिदेव यूनिटों से चर्चा कर रहे हैं। वे सिर्फ चर्चा ही नहीं कर रहे बल्कि इन्हें विजय का संकल्प भी दिलवा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के शक्ति केंद्रों पर ज्यादा जोर

एक खास बात यह भी है कि इस बार भाजपा का ज्यादा जोर ग्रामीण क्षेत्रों के शक्ति केंद्रों को लेकर है। पार्टी के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा इन शक्ति केंद्रों की व्यवस्थाएं संभाले हैं। वे अब तक सिमरोल मंडल के दतोदा, जोशी गुराडिया, सिमरोल, बाई ग्राम, चोरल, अंबा चंदन, भगोरा और हरसोला शक्ति केंद्रों को विजय का संकल्प दिलवा चुके हैं। इधर शहर क्षेत्रों में भी शक्ति केंद्रों को मजबूत करने का अभियान शुरू हो चुका है।

हमारा लक्ष्य हर एक शक्ति केंद्र को मजबूत बनाना है। हमने इसके लिए अभियान भी शुरू किया है। हम कार्यकर्ताओं को विजय संकल्प दिलवाने के साथ-साथ प्रत्येक बूथ पर विजय का संकल्प भी दिलवा रहे हैं।

-चिंटू वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष

पोहा-कचोरी के भाव के बराबर भोजन की थाली का रेट...

लोकसभा चुनाव के लिए भोजन का जो रेट तय किया गया है वह चौंकाने वाला है। इंदौर में जितने पैसे में एक प्लेट पोहा और एक कचोरी आती है उतने पैसे में दूसरे शहर में भोजन की थाली का भाव रखा गया है।

चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा हर वस्तु की कीमत तय की जाती है। चुनाव मैदान में उतरने वाले नेता के द्वारा उस कार्य पर किए जाने वाला खर्च इसी कीमत के हिसाब से जोड़ा जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के के साथ है। प्रक्रिया क्रिया के शुरू होने के साथ ही हर संसदीय क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा भाव तय करने का काम भी शुरू हो गया है। चुनाव का सीधा संबंध भोजन भंडारे से रहता है। चुनाव मैदान में उतरने वाले नेता अलग-अलग समूह के लोगों के लिए भोजन का आयोजन करते हैं। ऐसे में निर्वाचन कार्यालय के द्वारा जो भोजन की दर तय की जाती है वह महत्वपूर्ण होती है।

उस दर के हिसाब से भोजन करने वालों की संख्या को देखते हुए उतना पैसा संबंधित प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाता है। चुनाव कार्यालय ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भोजन की थाली के रेट तय कर दिया है। इस रेट के अनुसार भोजन की थाली भोपाल में सबसे महंगी महं और ग्वालियर में सबसे सस्ती रहेगी। जो रेट तय किया गया है उसके अनुसार भोपाल में भोजन की प्रति थाली 100, इंदौर में 80, जबलपुर में 77 रुपए और ग्वालियर में 40 होगी। मिनिमम कार्यकतार्ओं की संख्या 50 होगी।

नियत संख्या से ज्यादा कार्यकर्ता होने पर चुनाव कार्यालय को हिसाब देना पड़ेगा। इंदौर मैं पोहे की एक प्लेट बाजार में 20 की मिलती है और एक कचोरी 18 रुपए की मिलती है। इस तरह एक प्लेट पोहा और एक कचोरी 38 रुपए के होते हैं। ग्वालियर में तो भोजन की थाली का ही यह रेट रखा गया है।

आलू बुखारे

हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से लेकर त्वचा को चमकदार बनाने तक, सेहत को कई लाभ प्रदान करते हैं

पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करने से लेकर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और त्वचा की चमक बढ़ाने तक आलूबुखारे सेहत को कई अनगिनत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। चलिए गर्म दिनों में आलूबुखारे खाने के फायदों के बारे में जानते हैं।

गर्मियों के महीनों में मीठे-तीखे स्वाद वाले आलूबुखारे का सेवन करना काफी फायदेमंद माना जाता है। ये कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर समेत आवश्यक पोषक तत्व भरे होते हैं, जो गर्मियों में हमारी सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करने से लेकर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और त्वचा की चमक बढ़ाने तक आलूबुखारे सेहत को कई अनगिनत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। चलिए गर्म दिनों में आलूबुखारे खाने के फायदों के बारे में जानते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर- आलूबुखारे फेनोलिक यौगिकों और विटामिन सी सहित एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने और हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करते हैं।

पाचन स्वास्थ्य में सुधार- आलूबुखारे में घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, जो पाचन में सहायता करते हैं। ये कब्ज को रोकते हैं और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं ये फाइबर स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम को बनाए रखने में भी मदद करते हैं।

हृदय स्वास्थ्य- आलूबुखारे में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर मौजूद होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर और सूजन को कम करते हैं। ये रक्त वाहिका कार्य में सुधार करते है और हृदय स्वास्थ्य में योगदान देते हैं। बता दें, आलूबुखारे के नियमित सेवन से हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है।

हड्डियों का स्वास्थ्य- आलूबुखारे में विटामिन के, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए डाइट में आलूबुखारे को शामिल करें।

रक्त शर्करा नियंत्रण- आलूबुखारे में प्राकृतिक मिठास होती है, लेकिन बावजूद इसके इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ये रक्त शर्करा के स्तर में धीरे-धीरे वृद्धि करते हैं। इसलिए इन्हें डायबिटीज के लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है।

वजन नियंत्रण- आलूबुखारे में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इस तरह ये वजन नियंत्रित करने में मदद करता है। जो लोग अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो गर्मियों की डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं।

त्वचा का स्वास्थ्य- आलूबुखारे में विटामिन सी की मात्रा कोलेजन उत्पादन में योगदान करती है, जो त्वचा की लोच बनाए रखने में मदद करती है और उम्र बढ़ने के संकेतों को रोकती है। इसके अलावा आलूबुखारे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को मुक्त कणों और यूवी विकिरण से होने वाले नुकसान से बचाते हैं।

वजन घटाने के लिए रोजाना कितनी देर चलना चलना सहीं होता है

अगर आपका वजन बढ़ रहा है और आपके पास जिम जाकर वर्कआउट करने के लिए समय नहीं हैं तो आप बिलकुल भी चिंता न करें। अब सवाल बनता है कि वजन कम करने के लिए कितनी देर चलना चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाल कोच सिमरन कौर से जानते हैं रोजाना कितनी देर चलने से वजन कम होता है?

वजन कम करना बिलकुल भी आसान नहीं होता है। इसके लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुत से लोग हैवी वर्कआउट करने से भी डरते हैं। ऐसे में आप रोजाना टेहल कर वेट लॉस कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि वजन कम करने के लिए कितनी देर चलना चाहिए? आइए आपको बताते हैं न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाल कोच सिमरन कौर से जानते हैं रोजाना कितनी देर चलने से वजन कम होता है?

रिसर्च क्या कहती है : रिसर्च के मुताबिक, रोजाना पैदल चलना एक बढ़िया एरोबिक एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। CDC के अनुसार, रोजाना कम से कम 8 से 10 हजार कदम चलने से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

कितने कदम चलनी सही होता है? : एक्सपर्ट की मुताबिक, तो दिन में कम से कम 9000-10000 कदम चलने से वजन कम करने में मदद मिलती है, लेकिन इसके साथ एक्सरसाइज और डाइट का ख्याल रखना भी जरुरी है।

वजन घटाने के लिए कैसे वॉक करें? : बेहतर परिणाम के लिए वॉक करते समय ब्रिस्क पेस को मेंटेन करें यानी आपको न बहुत अधिक तेज वॉक करना है और ना ही बहुत धीमे चलना है। एक्सपर्ट की मानें तो सही रिजल्ट के लिए आपको हर हफ्ते में लगभग 150 मिनट वॉक करनी चाहिए। तभी आपको वजन कम करने में मदद मिल पाएगी।

किस समय वॉक करें? : सुबह 7 से 9 बजे के बीच का समय वॉक के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप सुबह पैदल नहीं चल पाते हैं, तो आप शाम और रात में पैदल चलकर भी आसानी से वजन कम कर सकते हैं।

पाचन संबंधित परेशानियां दूर होगी: पैदल चलने से पाचन संबंधित परेशानियां दूर होती है। वॉक करने से न केवल आपका वजन कम होगा, बल्कि इससे आपकी पाचन शक्ति भी बेहतर होगी। वॉक करने से गैस, एसिडिट और कब्ज से भी राहत मिलेगी।

मोटापे से सिर्फ हार्ट नहीं किडनी-लिवर को भी होता है नुकसान..

अगर आपका भी वजन अधिक है तो सावधान हो जाइए, अगर इसे समय रहते कंट्रोल न किया गया तो आपको गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। आमतौर पर बढ़े हुए वजन की समस्या को हृदय रोगों का कारक माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि इसके जोखिम यहीं तक सीमित नहीं हैं।

मोटापा गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसका खतरा लगभग हर उम्र के व्यक्ति में देखा जाता रहा है। मोटापे के शिकार लोगों में कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं, अधिक वजन और मोटापा की स्थिति न सिर्फ क्रोनिक बीमारियों का कारण बन सकती है साथ ही जिन लोगों को पहले से डायबिटीज-हार्ट की समस्या है उनके जोखिमों को और भी बढ़ा सकती है।

हृदय रोगों का खतरा

हृदय रोगों के लिए ब्लड प्रेशर बढ़े रहने को प्रमुख कारक माना जाता है। ये स्थिति दिल का दौरा, हार्ट फेलियर, एनजाइना और या असामान्य रूप से हृदय गति को भी बढ़ाने वाली हो सकती है। जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की समस्या रही है अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है तो ऐसे लोगों में जानलेवा हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी जोखिम बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि शरीर के अतिरिक्त वजन को कम करने से आपको हृदय रोग के इन जोखिम कारकों से बचाव में भी मदद मिल सकती है।

टाइप-2 डायबिटीज के हो सकते हैं शिकार

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया, अधिक वजन की समस्या आपको डायबिटीज का भी शिकार बना सकती है। टाइप-2 डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत अधिक हो जाता है। टाइप-2 डायबिटीज वाले लगभग 10 में से 9 लोगों का वजन अधिक देखा जाता रहा है। समय के साथ, हाई ब्लड शुगर के कारण हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी की बीमारी, आंखों की समस्याएं, तंत्रिकाओं का विकार होने का भी जोखिम बढ़ता जाता है।

लिवर में फैट की दिक्कत

मोटापे के दुष्प्रभाव सिर्फ ब्लड प्रेशर और हार्ट की दिक्कतों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर लिवर की सेहत पर भी हो सकता है। अधिक वजन की समस्या से फैटी लिवर रोग का जोखिम बढ़ जाता है। इस स्थिति में आपके लिवर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गंभीर लिवर डैमेज, सिरोसिस और यहां तक कि लिवर फेलियर भी हो सकती है। नॉनअल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (एनएएफएलडी) के बढ़ते वैश्विक जोखिमों के लिए शोधकर्ताओं ने मोटापे को प्रमुख कारकों में से एक माना है।

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या

जिन लोगों का वजन सामान्य से अधिक होता है उनमें हाई ब्लड प्रेशर और इससे संबंधित बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में खून का दबाव आपके रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर अधिक होने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा खतरा हृदय स्वास्थ्य पर देखा जाता रहा है और इसकी अनियंत्रित स्थिति हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का भी कारण बन सकता है।

चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए देश की इन ठंडी जगहों पर घूमने जाएं...

अगर आप भी अप्रैल की चिलचिलाती गर्मी पसंद नहीं हैं, तो फिर ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने के लिए भारत की इन शानदार जगहों पर जाने का प्लान बनाएं। अगर आप भी गर्मी से बचना चाहते हैं तो किसी सुंदर और ठंडी जगह पर छुट्टियां बिताने जा सकते हैं। पहाड़ियों को सुंदर नजारा और सुकून के पल बिताने के लिए ये जगहें सबसे बेस्ट हैं।

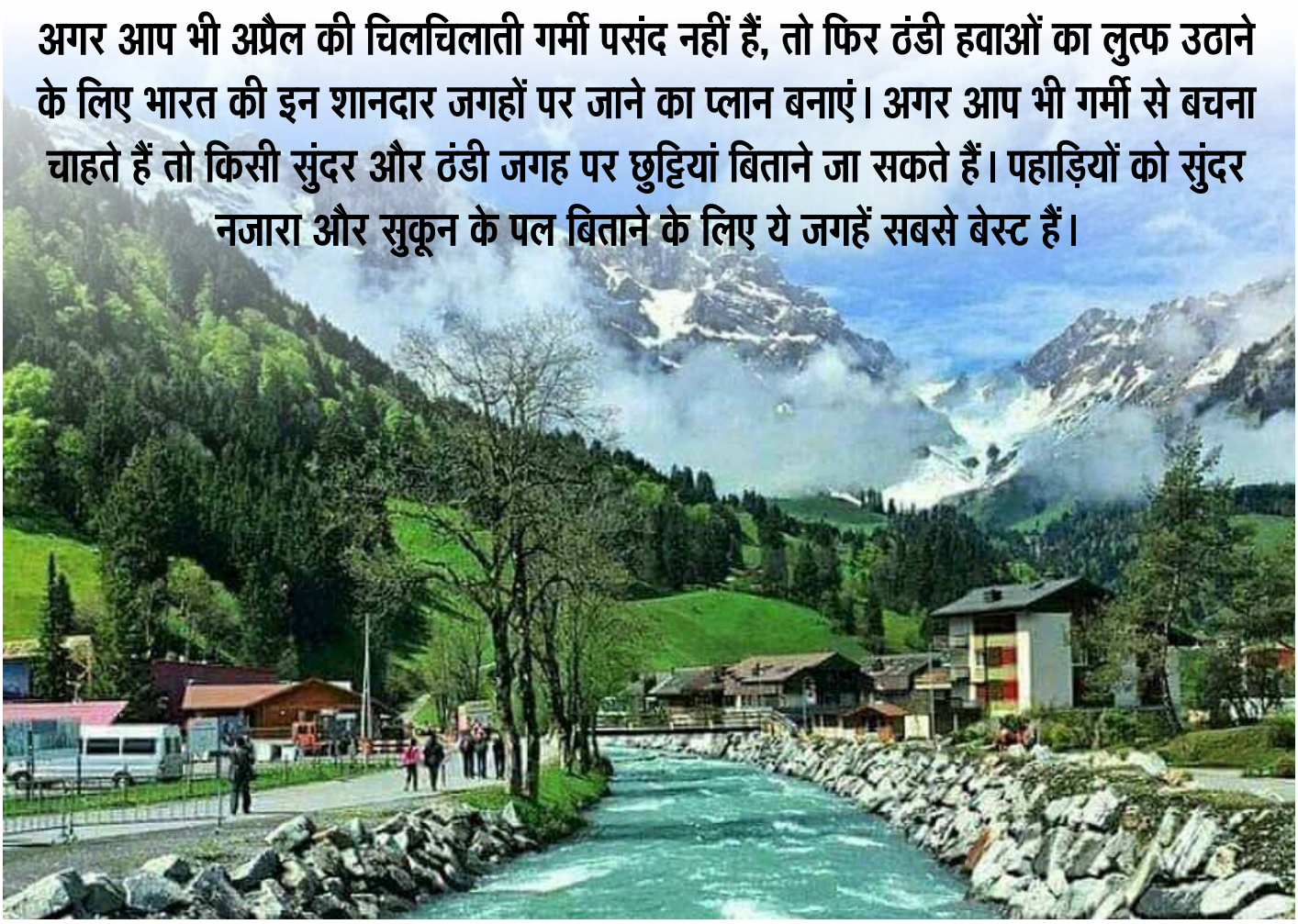

अप्रैल महीना ऐसा है जब पूरे देश में चिलचिलाती गर्मी शुरु हो जाती है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। कोई बीच पर समुद्र में डुबकी लगाने पहुंचता है, तो कोई ठंडी जगहों पर घूमने का प्लान बनाते हैं। अगर आप भी गर्मी से बचना चाहते हैं तो किसी सुंदर और ठंडी जगह पर छुट्टियां बिताने जा सकते हैं। चलिए हम आपको इस लेख में भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहें, जहां आप अपने दोस्त, परिवार और पार्टनर के साथ हसीन पल को एन्जॉय कर सकते हैं।

डलहौजी

पहाड़ियों को सुंदर नजारा और सुकून के पल बिताने के लिए डलहौजी सबसे बेस्ट जगह है। समुद्र तल से करीब 2 हजार मीटर की ऊंचाई पर मौजूद डलहौजी भारत का सबसे खूबसूरत और मनमोहक हिल स्टेशन माना जाता है। यहां पर ऊंचे-ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झील-झरने और देवदार के पेड़ इस हिल स्टेशन की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं। अप्रैल के महीने में चिलचिलाती गर्मी में भी डलहौजी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसलिए यहां आप अप्रैल से लेकर जुलाई तक भारी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं।

हर्षिल वैली

उत्तराखंड की हसीन वादियों में मौजूद हर्षिल वैली किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह एक ऐसी वैली है, जिसे एक्सप्लोर करने का सबका सपना होता है। यहां पर लगभग हर देशी और विदेशी पर्यटक देखा है। समुद्र तल से करीब 9 हजार से भी अधिक फीट की ऊंचाई पर मौजूद हर्षिल वैली का तापमान अप्रैल के महीने में 9 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहां पर आप ट्रेकिंग से लेकर यादगार फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।

पहलगाम

अप्रैल की गर्मी से बचने के लिए ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने के लिए आप जम्मू कश्मीर के पहलगान एक ऐसी जगह है, जहां किसी भी मौसम में घूमने का अलग ही मजा है। यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच तपमान रहता है। ठंडी हवाओं का मजा लेने के लिए देश के हर कोने से पर्यटक आते हैं। पहलगाम में आप तुलियन झील, शेषनाग झील, बीटा घाटी और मार्सर झील जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

गंगटोक

अप्रैल की भयानक गर्मी से बचने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की किसी शानदार जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप गंगटोक की हसीन वादियों में घूमने के लिए पहुंच जाना चाहिए। हिमालय की गोद में मौजूद इसे नॉर्थ ईस्ट इंडियां का सबसे ठंडा प्रदेश भी माना जाता है।

मनाली

गर्मियों में ठंडी का मजा लेने के लिए मनाली घूमने जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हिमालय की गोद में मौजूद मानली अप्रैल से लेकर जुलाई की भयानक गर्मी से बचने के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है।

वीकेंड पर बनाएं घूमने का प्लान

प्रकृति की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश का यह खूबसूरत गांव...

अधिकतर लोग हिमाचल का नाम सुनते ही शिमला या मनाली के बारे में सोचने लगते हैं। बता दें कि हिमाचल में इन जगहों के अलावा भी घूमने के लिए कई पर्यटक स्थल हैं। आप यहां पर तोष गांव एक्सप्लोर कर सकते हैं।

भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में फेमस है। भारत की अद्भुत प्राकृतिक नजारों के दीदार करने के लिए किसी पहाड़ी जगह पर जरूर जाना चाहिए। भारत के पहाड़, झील, झरने और वनस्पतियों से समृद्ध घने जंगल पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वैसे तो भारत में घूमने के लिए कई ऐसे जगहें हैं, जो आपके मन को मोह लेंगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश का लगभग हर स्थल दार्शनिक है। यहां पर गांवों से लेकर घाटी तक पर्यटकों का जमावड़ा लगता है। हर साल हिमाचल प्रदेश की सुंदरता को निहारने के लिए यहां पहुंचते हैं। अधिकतर लोग हिमाचल का नाम सुनते ही शिमला या मनाली के बारे में सोचने लगते हैं। बता दें कि हिमाचल में इन जगहों के अलावा भी घूमने के लिए कई पर्यटक स्थल हैं। जहां पर शांत वातावरण में आप आराम और सुकून के पल बिता सकते हैं। साथ ही आपका अधिक पैसा भी खर्च नहीं होगा। हिमाचल में शिमला-मनाली के अलावा तोष गांव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो बेहद खूबसूरत और बजट फ्रेंडली है। यहां पर आपको कई हसीन और खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी।

तोष में यहां घूमें

अगर आपको भी प्राकृतिक सुंदरता को पास से देखने का मन है, तो आप हिमाचल प्रदेश के पार्वती घाटी पर तोष नामक गांव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बता दें कि यह गांव समुद्र तट से करीब 7900 की ऊँचाई पर बसा है। शहर की भागदौड़ और शोर-शराबे से दूर इस गांव में आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। यहां पर आप झरने, झील और बर्फ से ढके पहाड़ आपके मन को मोह लेंगी।

तोष में ट्रेकिंग

इसके अलावा इस गांव में आपको कई तरह की एक्टिविटी का भी मजा ले सकते हैं। यहां पर ट्रेकिंग कर सकते हैं, जो आपके बजट में होगा। पार्टी के लिए भी यह बेहतरीन जगह है। आप चाहें तो तोष की लोकल पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं।

तोष घूमने का खर्च

हिमाचल के तोष गांव में स्टे के लिए आपको रुकने के लिए कोई बड़ा होटल नहीं मिलेगा। हांलाकि यहां पर रुकने के लिए रिजॉर्ट है। इसके साथ ही गांव वालों के घर पर भी आपको रुकने की व्यवस्था हो सकती है। यहां पर आपको प्रकृति को करीब से देखने का अनुभव मिल सकता है। यहां पर रहना और खाना अन्य जगहों से काफी सस्ता है।

कब पहुंचे तोष

अगर आप भी तोष जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सर्दियों में यहां जा सकते हैं। तोष में स्नोफॉल और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच आप बेहद अच्छा समय यहां पर बिता सकते हैं। हांलाकि तोष काफी ऊंचाई पर है, इसलिए यहां पहुंचने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है।

मां दुर्गा के 32 नाम, दूर करे भय और पीड़ा...

विपत्ति के समय भगवती मां दुर्गा का सच्चे मन से स्मरण एवं दुर्गा मंत्रों का जप अथवा दुर्गा जी के 32 नाम साधक की कवच के रूप में रक्षा करते हैं। नवरात्रि के दिनों में भक्तों को इन नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इन 32 नामों को मां दुर्गा, देवताओं को बताकर अंतर्ध्यान हो गईं। 'दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला' के रूप में मां दुर्गा के 32 नाम प्रसिद्ध है। इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्य की कभी कोई हानि नहीं होती। दुर्गा जी के 32 नामों के पाठ से व्यक्ति संकटों से छुटकारा पाता है। देवताओं की मां दुर्गा से प्रार्थना - एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा ने कहा, 'देवताओं! मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो, मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी।' मां दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, 'देवि! हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला, इससे सम्पूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने-अपने पद की प्राप्ति हुई है।

आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया। तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माहेश्वरी! ऐसा कौन सा उपाय है, जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकट में फंसे व्यक्ति की रक्षा करती हो। देवेश्वरी! यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताऐं।'' मां दुर्गा ने बताया रहस्य - देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर दयामयी माँ दुर्गा ने कहा- ''देवगण! सुनो, यह रहस्य अत्यन्त गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे बत्तीस नामों की माला सब

प्रकार की विपत्तियों का नाश करती है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। नास्तिक, दुराचारी, शठ और अभक्त व्यक्ति को छोड़कर जो मनुष्य मेरे 32 नामों का पाठ करता है वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो, दुर्भेद्य बन्धन में फंसा हो, राज्य दंड प्राप्त हो (सरकारी विवादों में फंसा हो) या युद्ध में शत्रुओं द्वारा घिर जाए तो इन बत्तीस नामों का 108 बार पाठ करने से वह सम्पूर्ण भय से मुक्त हो जाता है।'' घोर संकट से बचने के लिए इस नामावली का हजार, दस हजार अथवा लाख बार पाठ करें या किसी कर्मकाण्डी सुयोग्य आचार्य से करवाएं। विपत्ति के समय इससे सरल भयनाशक उपाय दूसरा कोई नहीं है।

नवरात्रि में जपें दुर्गा जी के बत्तीस नाम - दुर्गा, दुर्गार्तिशमनी, दुर्गापद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहन्त्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञानसंस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी

नवरात्र व्रत स्वस्थ रहने के लिए रामबाण...

नवरात्र व्रत का महात्म्य ज्योतिष, अध्यात्म के साथ-साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से और भी बढ़ जाता है। साल में छः मास के अंतराल पर रखे जाने वाले इस व्रत से पाचन तन्त्र को आराम मिलता है। आइए जानते हैं नवरात्र पर्व में छिपा स्वास्थ्य के लाभ।

9 अप्रैल, मंगलवार को चैत्र नवरात्रि के नौ दिनों के व्रतों का प्रारम्भ होगा, नवरात्रि की अष्टमी का व्रत 16 अप्रैल, मंगलवार को रखा जाएगा। देवी का पूजन एवं व्रत-उपवास नवरात्र पर्व के दौरान हमेशा चैत्र और आश्विन मास में किए जाने के पीछे वैज्ञानिक आधार निहित है। मौसम विज्ञान के अनुसार ये दोनों ही मास सर्दी-गर्मी की संधि के महत्वपूर्ण माह हैं। यूं तो ऋतुएं कहने को छह मानी जाती हैं, परन्तु यदि देखा जाए तो ये दो ही प्रकार की होती हैं, एक गर्मी और दूसरी सर्दी। शीत ऋतु का आगमन आश्विन माह से आरम्भ हो जाता है और ग्रीष्म का चैत्र मास में। ज्यों ही एक ऋतु का पदार्पण हुआ कि सम्पूर्ण भौतिक जगत में एक हलचल प्रारम्भ होने लगती है। पेड़, पौधे, वनस्पति जगत, जल, आकाश और वायुमंडल तक सब में परिवर्तन होने लगता है। ये दोनों मास दोनों ऋतुओं के संधिकाल हैं। अतः हमारे

स्वास्थ्य पर इनका विशेष प्रभाव पड़ता है।

व्रत रखने का वैज्ञानिक आधार - चैत्र मास में गर्मी के प्रारम्भ हो जाने से पिछले कई मास से जो रक्त का प्रभाव मंद था, अब वो हमारी नाड़ियों में तीव्र गति से प्रवाहित होने लगता है। केवल रक्त की ही बात नहीं यह नियम शरीर के वात, पित्त, कफ इन तीनों पर भी लागू होता है। यही कारण है कि संसार के अधिकांश रोगी इन मासों में या तो शीघ्र अच्छे हो जाते हैं या फिर पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जन्मपत्री में आयु पूर्ण हो जाने पर सांसारिक चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने संधि काल के इन्हीं मासों में शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए नौ दिन तक विशेष रूप से व्रत उपवास आदि का विधान बनाया है। नवरक्त संचारी वसन्त के इन मादक दिनों में मन में विषय वासना की नई तरंगें भी मन को खूब आंदोलित करती हैं, किन्तु यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इन नौ दिनों में आपने विधिपूर्वक व्रत उपवास का आश्रय लिया तो समझिए कि आगामी ऋतुकाल के लिए आपने अपने भीतर शक्ति का संचय कर लिया। जिसका फल आपको ये मिलेगा कि आगामी ऋतु परिवर्तन तक न तो कोई रोग, व्याधि और न किसी प्रकार की चित्त की विकलता ही आपको पीड़ित करेगी। उसमें प्रयुक्त गुणों को अपनी आत्मा में उतारिए तत्पश्चात् भूमि शयन कीजिए तो फिर देखिए आपकी आत्मिक शक्ति सम्पूर्ण रूप से विकसित होती है या नहीं? कभी-कभी तो ये देखकर विस्मित हो जाना पड़ता है कि अखंड ब्रह्माण्ड के संबंध संकेतों के पारखी हमारे ऋषि-मुनियों ने प्रकृतिप्रद नैसर्गिक सुअवसरों को परख कर हमें विशेष रूप से संस्कारित करने के कैसे-कैसे प्रयास किए हैं।

चैत्र नवरात्रि...जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। ये पर्व देशभर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के नौ दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों बिना कोई मुहूर्त देखे कई शुभ कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही लोग अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और नौ दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है... **शुभ मुहूर्त** : चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 08 अप्रैल को देर रात 11 बजकर 50 मिनट से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन यानी 09 अप्रैल को संध्याकाल 08 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए 09 अप्रैल को घटस्थापना है।

घटस्थापना का समय

09 अप्रैल को घटस्थापना समय सुबह 06 बजकर 02 मिनट से लेकर 10 बजकर 16 मिनट तक है। इसके अलावा 11 बजकर 57 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त है। आप इन दोनों मुहूर्त में घटस्थापना कर सकते हैं।

बन रहे ये शुभ योग

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 07 बजकर 32 से हो रहा है। ये दोनों योग संध्याकाल 05 बजकर 06 मिनट तक है।

घटस्थापना विधि

- सबसे पहले प्रतिपदा तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करके पूजा का संकल्प लें।
- फिर इसके बाद पूजा स्थल की सजावट करें और चौकी रखें जहां पर कलश में जल भरकर रखें। इसके बाद कलश को कलावा से लपेट दें।
- फिर कलश के ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखें।
- इसके बाद नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर कलश के ऊपर रख दें।
- इसके बाद धूप-दीप जलाकर मां दुर्गा का आवाहन करें और शास्त्रों में मां दुर्गा के पूजा-उपासना की बताई गई विधि से पूजा प्रारंभ करें।

हरियाणा में माता का सबसे अनोखा शक्तिपीठ, कैसे पहुंचे मां देवी के मंदिर...

चैत्र नवरात्रि चल रही है, ऐसे में सभी लोग ने मां दुर्गा के 9 स्वरुपों की पूजा कर रहे है और इसके साथ ही उपवास रख रहे हैं। अगर आप भी मां दुर्गा मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो हरियाणा में स्थित यह मंदिर देवी का खास महिमा के लिए जाना चाहता है। चैत्र नवरात्रि में हर कोई इस समय में मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग के पास इतना बजट नहीं होता है कि कहीं दूर दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं। अगर आप कहीं दूर दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं, तो परेशान न हो। आप माता के 51 शक्तिपीठों में से किसी भी एक शक्तिपीठ का दर्शने करने के लिए आप इस जगह पर जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में स्थित माता का फेमस शक्तिपीठ के बारे में, जहां आप नवरात्रि में दर्शन के लिए जा सकते हैं।

हरियाणा में स्थित है माता का शक्तिपीठ

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में माता का खास शक्तिपीठ मौजूद है। हरियाणा माता का केवल एक ही शक्तिपीठ है, जो बेहद ही खास माना जाता है। इस शक्तिपीठ का नाम श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर है। मान्यता के अनुसार, यहां देवी सती के दाएं पैर का टखना यानी घुटने के नीचे वाला भाग गिरा था। इसलिए यह मंदिर माता के आर्शीवाद के लिए सबसे खास है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी मंदिर में श्रीकृष्ण और बलराम का भी मुंडन हुआ था। साथ ही महाभारत युद्ध में विजय का आर्शीवाद लेने के लिए श्री कृष्ण इसी मंदिर में दर्शन के लिए आए थें।

मंदिर में माता को चढ़ाया जाता है : यहां माता को दूध, चीनी, शहद, घी और पानी चढ़ाने का विराज है। इसके अलावा माता को सोलह श्रृंगार की चीजें भी चढ़ाई जाती हैं।

कैसे पहुंचे श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर?

रेलवे स्टेशन और बस अड्डा-कुरूक्षेत्र रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से आप यहां पहुंच सकते हैं। वहीं आप नजदीकी हवाई अड्डी- दिल्ली और चंडीगढ़ में स्थित हवाई अड्डे से आप यहां दर्शन कर सकते हैं।

घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए इस तरह करें गणेशजी की पूजा

भगवान शंकर जी के सुत और भवानी के नंदन भगवान गणेश विघ्नहर्ता के साथ ही बुद्धि प्रदाता भी हैं। विद्यार्थियों को इनकी आराधना करने से उनके बौद्धिक स्तर में वृद्धि के साथ ही लेखन शैली में विकास होता है। भगवान शंकर जी के सुत और भवानी के नंदन भगवान गणेश विघ्नहर्ता के साथ ही बुद्धि प्रदाता भी हैं। विद्यार्थियों को इनकी आराधना करने से उनके बौद्धिक स्तर में वृद्धि के साथ ही लेखन शैली में विकास होता है। गणेश जी लेखनी के धनी हैं, इसलिए भगवान वेद व्यास ने जब महाभारत की रचना के विषय में विचार किया तो उन्होंने इसे लिखने के लिए गणेश जी का चुनाव किया।

महाभारत लिखने में गणेश जी को क्यों लगे 3 साल? : महाभारत की कथा इतनी बड़ी है कि जिसे लिखने में किसी अन्य देवता को सदियां लग जाती किंतु गणेश जी की लेखन गति बहुत तेज थी, फिर भी उन्हें लिखने में तीन सालों का समय लगा। महाभारत लिखते समय गणेश जी ने शर्त रख दी की उनकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि यह तो ठीक है लेकिन आप हर श्लोक को समझ कर ही लिखेंगे। बताते हैं कि गजानन को जितना समय श्लोक का अर्थ समझने में लगता था, उतनी देर में व्यास जी अगले श्लोक की रचना कर लेते थे।

इस तरह करें भगवान गणेशजी के दर्शन : मान्यता है कि गणेश जी के पीछे पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमेशा सामने से ही गणेश जी के दर्शन करने चाहिए। गणेश जी के मंदिर से बाहर निकलते समय ध्यान रखें कि हाथ जोड़ कर पीछे की तरफ उलटे कदम चलते हुए ही बाहर निकलें।

गणपति के साथ करें माता लक्ष्मी की पूजा : भगवान विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी एक दिन काफी दुखी भाव से अपने पति की सेवा कर रही थीं। उनके दुख का कारण उनके किसी संतान का न होना था। जैसे ही यह बात माता पार्वती को पता चली तो वह तुरंत ही अपने बालक गणेश के साथ पहुंचीं और उन्हें माता लक्ष्मी की गोद में बैठा कर कहा गणेश माता लक्ष्मी के भी पुत्र हैं। इस पर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि जब तक कोई उनके साथ भगवान गणेश की पूजा नहीं करेगा, उसे कभी भी सुख- समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। यही कारण है कि भगवान गणेश की पूजा लक्ष्मी जी के साथ भी की जाती है।

जैन धर्म में मृत्यु पर इस तरह विजय प्राप्त करते हैं संत, काफी कठिन है समाधि की अनोखी परंपरा

हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी महासमाधि ली जाती है। लेकिन जैन धर्म की समाधि को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है। तो आज हम आपको सल्लेखना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी महासमाधि ली जाती है। लेकिन जैन धर्म की समाधि को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है। जैसे जैन धर्म में समाधि के क्या मायने होते हैं। समाधि कैसे ली जाती है और सल्लेखना क्या होता है। साथ ही इसको खुदकुशी क्यों कहा जाता है। ऐसे में अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल रहते हैं। तो यह आर्टिकल आपके लिए है। क्योंकि आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

क्या होता है सल्लेखना : आपको बता दें कि जैन संतों द्वारा ली जाने वाली समाधि को सल्लेखना कहा जाता है। जैन धर्म के मुताबिक सल्लेखना एक तरह की आत्महत्या है। सल्लेखना के जरिए जैन संत नश्वर जीवन की मुक्ति के बिना ही विशेष कर्मकांड के प्राप्त करते हैं। लेकिन जैन धर्म में सल्लेखना से जुड़े कुछ नियम भी मौजूद होते हैं। जैन धर्म में यदि किसी संत

को सल्लेखना या समाधि लेते है। तो उनको संपत्ति संचय, झूठ बोलना, अहिंसा और चोरी जैसे कृत्यों को त्याग करना पड़ता है। क्योंकि असल में इस धर्म में सल्लेखना की परंपरा बेहद खास मानी जाती है। वहीं इस सल्लेखना परंपरा का पालन मृत्यु आने पर किया करते हैं। जब जैन धर्म में किसी को लगता है कि उसकी मृत्यु आने वाली है। वहीं कुछ दिनों में उसका शरीर प्राण को छोड़ सकता है। तब व्यक्ति खुद से भोजन और जल का त्याग करता है। बता दें कि दिगंबर जैन शास्त्र के मुताबिक इसको ही महासमाधि या सल्लेखना कहा जाता है।

बताया जाता है कि सल्लेखना यानी महासमाधि का पालन करना बेहद कठिन होता है। सल्लेखना के दौरान शरीर को अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। इस परंपरा का अपना इतिहास भी है। इसके अनुसार, 'जैन' शब्द की उत्पत्ति जिस से हुई है, जिसका अर्थ 'विजेता' होता है। जैन धर्म में मृत्यु को विजय माना गया है।

जैन धर्म के संत जब सल्लेखना लेते हैं, तब मृत्यु का समय विजय प्राप्त करने के समान होता है। इसी वजह से सल्लेखना के दौरान इन नियमों का पालन करना इस धर्म में सबसे ज्यादा अहम माना गया है।

भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित हैं यह मंदिर...

दर्शन मात्र से पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं

भगवान श्रीहरि विष्णु को इस संसार का पालनहार माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वहीं श्रीहरि विष्णु का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए इन फेमस मंदिरों में दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप भी भगवान श्रीहरि विष्णु के परम भक्त हैं, तो हम आपको भगवान विष्णु को समर्पित 5 फेमस मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे में आप भी इन मंदिरों में दर्शन कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु को इस संसार का पालनहार माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वहीं भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए लोग गुरुवार का व्रत करते हैं और श्रीहरि विष्णु की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। वहीं लोग भगवान विष्णु के मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान श्रीहरि विष्णु के परम भक्त हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको भगवान विष्णु को समर्पित 5 फेमस मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे में आप भी इन मंदिरों में दर्शन कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

बद्रीनाथ

उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा के किनारे श्री बद्रीनाथ विराजमान है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 'चार धाम' तीर्थस्थल में शामिल है। भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित 108 मंदिरों में शामिल है। तमिल संतों द्वारा बद्रीनाथ मंदिर का छठी से 9वीं शताब्दी के बीच उल्लेख किया था।

वेंकटेश्वर मंदिर

वेंकटेश्वर मंदिर भगवान विष्णु का सबसे पुराना और सबसे फेमस मंदिर है। तिरुपति के पास तिरूमाला पहाड़ी पर भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर स्थित है। हर साल यहां पर अनगिनत संख्या में लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

रंगानाथ मंदिर

भगवान विष्णु को समर्पित रंगानाथ मंदिर दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित है। यह भगवान विष्णु के विशेष मंदिरों में से एक है। बताया जाता है कि भगवान विष्णु के इस मंदिर में श्रीराम ने लंका विजय करने के बाद लौटते समय यहां पर पूजा-अर्चना की थी।

जगन्नाथ मंदिर

जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर भी चार धाम में शामिल है। बता दें कि जगन्नाथ पुरी मंदिर से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। हर साल जगन्नाथ पुरी से निकलने वाली रथ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं।

द्वारिकाधीश मंदिर

द्वारिकाधीश मंदिर भगवान श्रीहरि विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण को समर्पित है। करीब 2000 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण भगवान श्रीकृष्ण के पोते वज्रनाभ ने करवाया था। यह मंदिर विशेष इसलिए है, क्योंकि यह द्वारिका में स्थित है। वहीं द्वारिका श्रीकृष्ण की नगरी थी। द्वारिकाधीश मंदिर चार धाम तीर्थस्थान में शामिल है।

स्किन को हेल्दी रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, त्वचा होगी चमकदार

त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या नहीं करते? हालांकि फेस को हेल्दी रखना भी काफी जरुरी है। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए इस लेख में हम बताएंगे यह बेहतरीन टिप्स। इन टिप्स को अपनाकर त्वचा खीली-खीली नजर आएगी। जब आप अपनी त्वचा की देखभाल करें तो स्थिरता लाना काफी महत्वपूर्ण है। चमकदार त्वचा पाने के लिए क्या नहीं करते लेकिन फिर भी फेस पर निखार नहीं आता। त्वचा को स्वस्थ रखना भी बहुत जरुरी है। वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषण से त्वचा निखार खो देती है जिस वजह से फेस डल नजर आने लगता है। भाग-दौड़ भरी जिंदगी में आजकल लोग अपनी स्किन का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते हैं जिस वजह से हमारी त्वचा दिनो-दिन बेजान नजर आने लगती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे अपनी त्वचा को हेल्दी कैसे रखें। आइए आपको इन टिप्स के बारे में जरुर बताते हैं। गंदगी, तेल और अशुद्धियों को हटाने के लिए अपने चेहरे को दिन में दो बार किसी सौम्य क्लींजर से धोएं। कठोर साबुनों से बचें जो आपकी त्वचा से उसका प्राकृतिक ऑयल छीन सकते हैं।

मॉइस्चराइज करें

अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए अपनी स्किन टाइप अनुसार उपयुक्त मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। मॉइस्चराइजिंग त्वचा की बैरियर कार्यप्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है और यह सूखापन और जलन को रोकता है।

हाइड्रेटेड रहें : अपनी त्वचा को अंदर से बाहर तक हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पिएं। डिहाइड्रेटेड स्किन को सुस्त और ड्राई दिखाई दे सकती है, इसलिए दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें।

स्वस्थ आहार लें

अपने आहार में भरपूर मात्रा में फल, सब्जियाँ और एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। ये पोषक तत्व आपकी त्वचा को पोषण देने और स्वस्थ रंगत को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

पर्याप्त नींद लें

स्वस्थ त्वचा के लिए हर रात 7-8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें। नींद आपकी त्वचा को मरम्मत और पुनर्जीवित करने की अनुमति देती है, जिससे त्वचा चमकदार और अधिक तरोताजा दिखती है।

तनाव को प्रबंधित करें

लगातार तनाव आपकी त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे मुंहासे और त्वचा संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देने के लिए तनाव कम करने वाली गतिविधियों जैसे ध्यान, योग या गहरी सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करें।

शराब सीमित करें

बेजान त्वचा से छुटकारा पाने के लिए धूम्रपान और शराब से बचें। क्योंकि धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। स्वस्थ त्वचा बनाए रखने के लिए धूम्रपान छोड़ें और सीमित मात्रा में शराब पियें।

सौम्य स्किन केयर उत्पादों का उपयोग करें : ऐसे स्किन केयर के उत्पाद चुनें जो कोमल हों और आपकी त्वचा के प्रकार के लिए उपयुक्त हों। कठोर रसायनों या सुगंध वाले उत्पादों से बचें जो आपकी त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं।

डीकोलेटेज के बारे में न भूलें

अपनी त्वचा की देखभाल की दिनचर्या को अपनी गर्दन और छाती क्षेत्र तक बढ़ाएं, क्योंकि ये क्षेत्र भी उम्र बढ़ने के लक्षण दिखा सकते हैं। याद रखें कि जब आप अपनी त्वचा की देखभाल करें तो स्थिरता लाना काफी महत्वपूर्ण है। नियमित स्किन केयर दिनचर्या पर कायम रहें।

त्वचा को धूप से बचाएं : स्किन की बेहतर देखभाल के लिए हर दिन एसपीएफ 30 या इससे अधिक वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं, यहां तक कि बादल वाले दिनों में भी इसे जरुर लगाएं। सनस्क्रीन आपकी त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है जो समय से पहले बूढ़ा होने और त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं।

ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए आज ही छोड़ दें ये आदतें...

ह मारे दिमाग का कुल भार एक किलोग्राम से कुछ अधिक होता है। दिमाग को पूरे शरीर का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसलिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपने दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे शरीर में भले ही मस्तिष्क छोटा सा दिखने वाला अंग है। दिमाग को पूरे शरीर का मास्टरमाइंड माना जाता है। विचार, गति और भावनाओं को कंट्रोल करने के साथ ही शरीर के किस अंग को कौन सा और किस तरह से काम करना है, यह सबकुछ दिमाग ही निर्धारित करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे दिमाग का कुल भार एक किलोग्राम से कुछ अधिक होता है। लेकिन यह पावरहाउस से कम नहीं होता है।

आपको बता दें कि मस्तिष्क में अरबों तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो सब जरूरी कार्यों को संभव बनाती हैं। मस्तिष्क की इन कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहा जाता है। यह शरीर के बाकी हिस्सों में जानकारी भेजने का काम करती हैं। यदि दिमाग में किसी तरह की समस्या होती है, तो शरीर के सभी अंगों को मिलने वाली जानकारी में भी दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्टस् दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहने की सलाह देते हैं।

ब्रेन संबंधी बढ़ती समस्याएं

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो हमारे शरीर की सबसे मूल्यवान संपत्ति दिमाग है। जो शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से ब्रेन की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपने दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन क्या आप अपने ब्रेन का ख्याल रखते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में इन आदतों से बचे रहना बेहद जरूरी है।

धूम्रपान की आदत

धूम्रपान न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य बल्कि मस्तिष्क के लिए भी नुकसानदायक होता है। धूम्रपान करने से फेफड़ों की बीमारी होती है और ब्रेन पर भी इसका निगेटिव असर पड़ सकता है। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। जिसके कारण क्रोनिक इंफ्लामेशन भी हो सकता है। ऐसी स्थिति ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने के साथ ही संज्ञानात्मक गिरावट की भी वजह बन सकती है। धूम्रपान करने वाले लोगों में डिमेंशिया रोग होने की संभावना होती है। ऐसे में आप धूम्रपान की आदत को छोड़कर दिमाग को स्वस्थ रख सकते हैं।

सेंडेंटरी लाइफस्टाइल

व्यायाम न करना और शारीरिक सक्रियता की कमी भी हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंता सकती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल गतिहीन है, तो इसके सकारात्मक

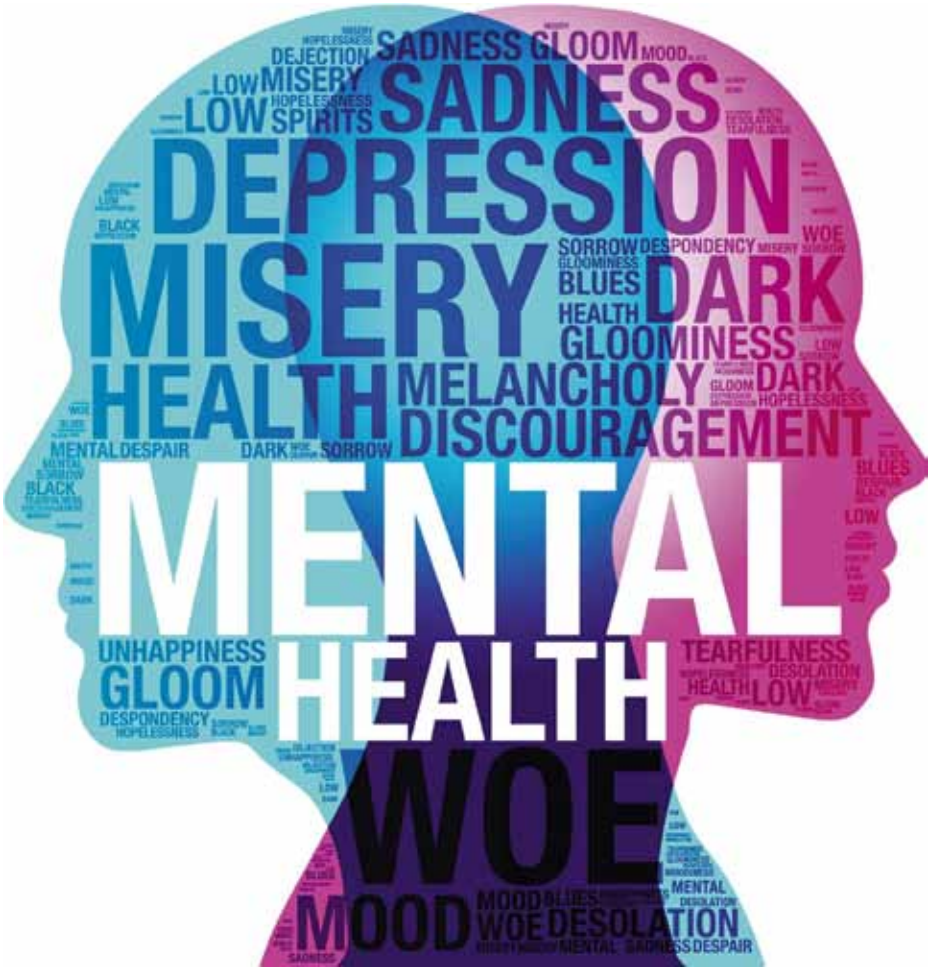

बदलाव लाना जरूरी है। क्योंकि दिनभर बैठे रहना या अधिक अस्थिरता की वजह से हृदय रोग, मोटापा और मधुमेह समेत कई स्वास्थ्य समस्याएं आपको घेर सकती हैं। यह सभी स्थितियां और आदतें आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती हैं। सेंडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण भी डिमेंशिया हो सकता है। ऐसे में मस्तिष्क को हेल्दी रखने के लिए रोजाना व्यायाम आदि करना चाहिए।

पर्याप्त नींद न लेना : जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो इसका आपके दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है। क्योंकि आपके दिमाग को भी आराम करने और ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। ऐसे में नींद पूरी न होने पर स्मृति हानि, संज्ञानात्मक गिरावट और मूड में बदलाव जैसी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। कुछ रिसर्चों की मानें तो नींद की कमी होने पर चिड़चिड़ापन और चीजों को याद रख पाने में दिक्कत होती है। ऐसे में मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए।

सुपरस्टार राम चरण के साथ शेयर करेंगी स्क्रीन जान्हवी कपूर

जान्हवी कपूर राम चरण की आगामी तेलुगु फिल्म में अभिनय करने के लिए तैयार हैं, जिसका निर्देशन बुच्ची बाबू सना करने वाले है। 6 मार्च को जान्हवी कपूर के जन्मदिन पर इस खबर की आधिकारिक घोषणा की गई। जान्हवी कपूर का शेड्यूल बहुत व्यस्त है। एक्ट्रेस जो अपनी तीन रिलीज के लिए तैयार है, अब 'देवरा' के बाद एक और तेलुगु फिल्म में अभिनय करने के लिए तैयार है।एक्ट्रेस अब राम चरण की 16वीं फिल्म में उनके साथ स्क्रीन स्पेस साझा करेंगी, जिसे बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। आधिकारिक घोषणा आज, 6 मार्च को की गई।

जान्हवी कपूर के जन्मदिन पर, प्रोडक्शन हाउस माइथ्री मूवी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के साथ फिल्म की खबर को आधिकारिक बना दिया। कैप्शन में लिखा है, 'RC16 के लिए बोर्ड पर दिव्य सुंदरता का स्वागत करते हुए मंत्रमुग्ध कर देने वाली जान्हवी कपूर को जन्मदिन की शुभकामनाएं।' फिल्म का निर्देशन बुच्ची बाबू सना करेंगे। उन्होंने जान्हवी का भी स्वागत किया और लिखा, "आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं जान्हवी कपूर, आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।"

इससे पहले जान्हवी कपूर के पिता बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस खबर की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था, ''मेरी बेटी पहले ही जूनियर एनटीआर के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर चुकी है। वह यहां सेट पर बिताए गए हर दिन को पसंद करती है। जल्द ही वह राम चरण के साथ भी एक फिल्म शुरू करेंगी. ये दोनों लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं. वह बहुत सारी तेलुगु फिल्में देख रही हैं और उनके साथ काम करके वह धन्य महसूस करती हैं।

दीपिका की प्रेग्नेंसी के कारण रुकी करण की अगली फिल्म

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले के उत्सव में, यह जोड़ी एक साथ सबसे प्यारी लग रही थी और दीपिका पादुकोण के चेहरे पर गर्भावस्था की चमक काफी स्पष्ट थी।

कुछ दिन पहले रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने घोषणा की थी कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। जोड़े ने घोषणा की कि वे सितंबर के महीने में अपनी छोटी सी खुशी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले के उत्सव में, यह जोड़ी एक साथ सबसे प्यारी लग रही थी और दीपिका पादुकोण के चेहरे पर गर्भावस्था की चमक काफी स्पष्ट थी। अब, एक ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि करण जौहर का अगला प्रोडक्शन वेंचर रुका हुआ है क्योंकि दीपिका पादुकोण मातृत्व अवकाश लेंगी।

जूम की एक रिपोर्ट के अनुसार, करण जौहर के पास एक फिल्म है जिसे वह दीपिका पादुकोण के साथ करना चाहते हैं लेकिन अभिनेत्री मातृत्व अवकाश पर जाएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक लेखक-समर्थित परियोजना है और दीपिका को इसकी स्क्रिप्ट पसंद है। लेकिन अभिनेत्री ने कथित तौर पर करण जौहर से कहा कि वह उनका इंतजार न करें और वह किसी और के साथ इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन करण जौहर उनके लिए इंतजार करने को तैयार हैं और चाहते हैं कि वह अपने मातृत्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सूत्र का कहना है कि करण जौहर के पास तब तक काम करने के लिए कई अन्य प्रोजेक्ट हैं। अब क्या करण जौहर की वो मिठाई नहीं है. हालाँकि, करण जौहर या दीपिका पादुकोण की ओर से इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। मशहूर फिल्म निर्माता ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी खत्म करने के लिए आलिया भट्ट का भी इंतजार किया क्योंकि वह गर्भवती थीं।

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

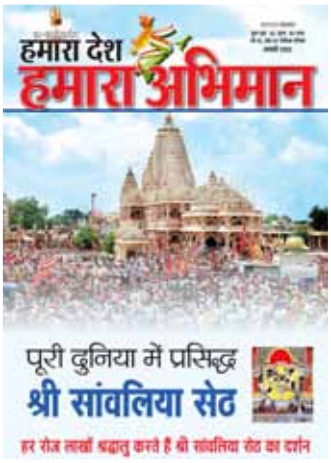

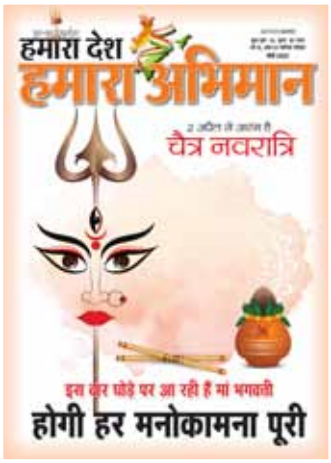

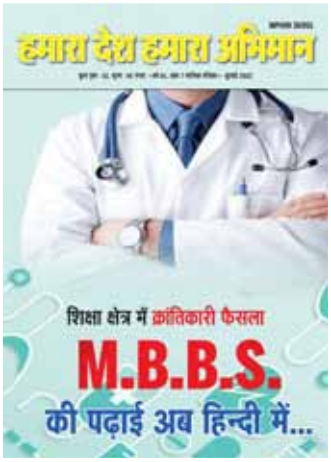

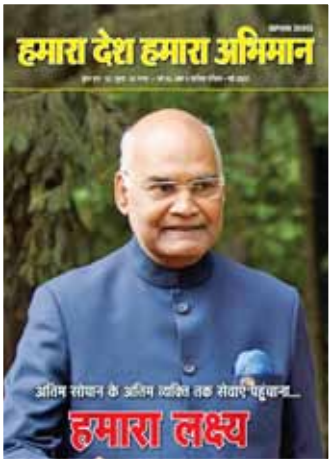

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136

मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः'
मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः

अर्थ : हे भगवान शिव, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और पृथ्वी पर फिर से जीवन कायम करने के लिए ब्रह्मांड के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। हे भगवान, आप नीलकंठ हैं क्योंकि आपका गला नीला है। हम हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करते हैं प्रभु।'